● वर्ष-5

● अंक-198

रायपुर, रविवार
05 अप्रैल 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› मुख्यमंत्री साय का बड़ा दावा...

आईआईएम के 15वें दीक्षांत समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए शामिल

वैश्विक सोच के साथ अपने कौशल का करें उपयोग

रायपुर। विदेश मंत्री एस. जयशंकर आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। वह नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अथिति के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच युवाओं की भूमिका और उनकी तैयारी पर विस्तार से चर्चा की।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने भाषण में कहा कि सीमा पार होने वाली घटनाएं सीधे हमारे जीवन और करियर को प्रभावित करती हैं। छात्रों को न केवल अपनी पढ़ाई या क्षेत्र तक सीमित न रहने बल्कि दुनिया में हो रहे राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन को भी समझने की जरूरत है। भारत ने बीते वर्षों में आर्थिक मोर्चे पर मजबूत पकड़ बनाई है और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान को और सशक्त किया है। कठिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में भी भारत ने स्थिरता बनाए रखी, जो उसकी नीतियों और क्षमता को दर्शाता है। बुनियादी ढांचे और तकनीकी विकास पर बात करते हुए विदेश मंत्री एस। जयशंकर ने कहा कि देश में सड़कों, रेल नेटवर्क और बंदरगाहों के

विस्तार के साथ-साथ डिजिटल क्रांति ने व्यापार और दैनिक जीवन को अधिक सुगम बनाया है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुले हैं। खाद्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करने की जरूरत है।

विदेश नीति को लेकर उन्होंने कहा कि यह केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार और उद्योग को अंतरराष्ट्रीय बाजार में आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे वैश्विक सोच के साथ अपने कौशल का उपयोग करें और भारत का नाम दुनिया में ऊंचा करें। वहीं सफलता मंत्र देते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में मौजूद है, इसलिए निरंतर मेहनत, नेतृत्व क्षमता और मजबूत संबंध बनाना बेहद जरूरी है।

तेजी बदल रहा दुनिया

एस. जयशंकर ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है। देशों के बीच ताकत का संतुलन बदल रहा है। तकनीक, ऊर्जा और संसाधनों के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। ऐसे में देशों और कंपनियों को अब जोखिम कम करने, विविधता लाने और नए विकल्प खोजने पर ध्यान देना पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि भारत में आज आशावाद का माहौल है, जो दुनिया के कई हिस्सों में नहीं दिखता। इसका कारण पिछले 10 साल की प्रगति है। उन्होंने डिजिटल क्रांति का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने इसे सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि जीवन में प्रभावी तरीके से लागू भी किया है।

विदेश मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए कहा कि खाद्य, स्वास्थ्य, ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपनी क्षमता मजबूत करना जरूरी है। जहां खुद करना संभव न हो, वहां भरोसेमंद साझेदारी जरूरी है।व्यापार को आसान बनाने, बेहतर माहौल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवे, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट और जलमार्ग देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही डिजिटल टूल्स और नेतृत्व से सुशासन मजबूत हुआ है और लोगों का जीवन आसान बनाना लगातार जारी प्रक्रिया है।

कारोबार के लिए दुनिया को समझना जरूरी

जयशंकर ने कहा कि छोटे कारोबार, स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए अवसर बढ़े हैं। देश में शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ी है और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। तकनीक, इनोवेशन और उद्यमिता भारत की स्थिति को और मजबूत करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि आज के कारोबार के लिए दुनिया को समझना जरूरी है। अब भारत में रहने वाले लोग भी विदेशी प्रोडक्ट, पार्टनर और सेवाओं से जुड़े हैं। उन्होंने युवाओं से वैश्विक घटनाओं में रुचि लेने की अपील की और कहा कि यह करियर के लिए फायदेमंद होगा।

एलडीएफ सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू: पीएम मोदी

तिरुवल्ला (केरल)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और केरल में भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सत्ता में आयेगा. मोदी ने पथनमथिट्टा जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राजग की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एलडीएफ सरकार की विदाई करने के लिए काफी उत्साह दिखाया है.

राज्य विधानसभा की 140 सीट के लिए नौ अप्रैल को चुनाव होगा. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा राज्य की सत्ता में आती है, तो वह केरल में विकास सुनिश्चित करेगी, जैसा कि उसने गोवा

और पूर्वोत्तर के सात राज्यों में से छह में किया है, जहां वह सत्ता में है और वहां ईसाई आबादी काफी अधिक है.

उन्होंने कहा कि केरल में अपार संभावनाएं हैं, फिर भी विकास की दौड़ में यह अन्य राज्यों से पीछे है. उन्होंने आरोप लगाया कि केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की स्थिति खराब है, क्योंकि एलडीएफ और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने इस पर ध्यान नहीं दिया.प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र में राजग सरकार ने केरल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, जबकि राज्य में अभी तक भाजपा की सरकार नहीं रही है. उन्होंने कहा कि राजग सरकार ने केरल में विकास पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकारों की तुलना में पांच गुना अधिक खर्च किया है। जब केरल में भाजपा की 'डबल इंजन' वाली सरकार सत्ता में आएगी, तो सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और ''यह मोदी की गारंटी है.'' प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश में, अगर किसी समूह को राजग की नीतियों से सबसे ज्यादा फायदा होता है, तो वे ''मेरी माताएं, बहनें, बेटियां और महिलाएं'' हैं. मोदी ने केरल से रोजगार के लिए युवाओं के पलायन का भी जिक्र किया और कहा कि यह राज्य की सबसे बड़ी समस्या है।

बंगाल में अमित शाह के रोड़ शो के दौरान हुआ हंगामा, तीन जुर्म दर्ज

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता रोड शो के दौरान हुए हंगामे को लेकर तीन एफ्आईआर दर्ज हो चुकी हैं। भवानीपुर से भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी के नामांकन के मौके पर आयोजित रोड शो का तृणमूल कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिससे कार्यक्रम अव्यवस्थित हुआ। दक्षिण कोलकाता के कालीघाट और हजरा सहित कई इलाकों में तनाव और नारेबाजी देखने को मिली। पुलिस के मुताबिक, दो एफ्आईआर अलीपुर थाने में दर्ज हुई हैं। एक चुनाव आयोग की शिकायत पर आचार संहिता उल्लंघन को लेकर और दूसरी स्वत: संज्ञान में लेकर दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक सख्ती दिखाकर एक संयुक्त बीडीओ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।

रायपुर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स-2026 में कर्नाटक के 9 पहलवानों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 4 सिद्दी समुदाय से थे। इन चार पहलवानों में से तीन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया जबकि एक को रजत पदक मिला। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहलवानों में मनीषा जुआवा सिद्दी (76 किग्रा), रोहन एम डोड़ामणि (ग्रीको रोमन 60 किग्रा) और प्रिंसिता पेदरू फर्नांडिस सिद्दी (68 किग्रा) शामिल हैं जबकि शालिना सेयर सिद्दी (57 किग्रा) को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

सीएम साय ने भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में जनसमर्थन की अपील की

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज पश्चिम बंगाल के नयाग्राम, गोपीबल्लवपुर, झारग्राम और बिनपुर विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन दें और राज्य में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएं। नामांकन कार्यक्रम में उपस्थित जनता का उत्साह और समर्थन अभूतपूर्व था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर उमड़ा यह जनसैलाब और हर वर्ग का समर्थन स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि बंगाल की धरती पर इस बार कमल खिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल की जनता बदलाव के लिए पूरी तरह संकल्पित है और टीएमसी की सरकार से मुक्त होकर भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

कार्यक्रम के दौरान सीएम साय ने मतदाताओं को विश्वास दिलाया कि भाजपा शासन में विकास और जनता की सुरक्षा प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अन्य सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भाजपा सरकार

काम करेगी। वहीं, स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनता ने भी इस अवसर पर सक्रिय भागीदारी दिखाई। नामांकन कार्यक्रम के दौरान रोड शो और सभा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जिससे भाजपा प्रत्याशियों को जनसमर्थन का मजबूत संदेश मिला।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा केवल चुनावी नारा नहीं देती, बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान करने और राज्य में विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस चुनाव में भाजपा को अपना समर्थन दें और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन की लहर को मजबूत करें। इस अवसर पर क्षेत्रीय नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जनता को जोड़ने और समर्थन जुटाने में सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता को भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जागरूक करना और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत जनमत तैयार करना था।

प्रमुख समाचार

बदलते युद्ध के लिए संयुक्त तैयारी जरूरी: सीडीएस

नई दिल्ली । चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल (सीडीएस) अनिल चौहान ने शनिवार को श्रीनगर स्थित चिनार कोर के तहत अहम इलाकों का दौरा किया और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास सुरक्षा स्थिति और सेना की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उत्तरी कश्मीर में तैनात बलों की तैयारियों, सामंजस्य और पेशेवर क्षमता की सराहना की। बारामूला में उन्हें भविष्य के युद्ध में बलों के

उपयोग और नई तकनीकों के समावेशन को लेकर जानकारी दी गई। अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीडीएस ने कहा कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, इसलिए अब केवल एक क्षेत्र पर आधारित रणनीति पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सफलता के लिए थल, वायु, समुद्री, साइबर, अंतरिक्ष और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में एक साथ काम करना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि बेहतर समन्वय, संयुक्त प्रशिक्षण और एकीकृत कमान व्यवस्था से ही प्रभावी परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। जनरल चौहान ने कहा कि बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीक अपनाने, मानसिक रूप से मजबूत रहने और मिलकर तैयारी करने की जरूरत है।

पिनाराई विजयन दक्षिणपंथी ताकतों की कठपुतली : राहुल

नई दिल्ली । केरल विधानसभा चुनाव के प्रचार में अब सियासी हमलों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केरल के अलप्पुझा, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ एलडीएफ और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में दो ननों पर हुए हमले और मणिपुर में चर्च जलाए जाने की घटनाओं का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो इन हरकतों के पीछे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का उन लोगों के साथ पार्टनरशिप यानी साठगांठ है जो अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कोच्चि की रैली में कहा कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट अब सिर्फ नाम का लेफ्ट रह गया है। असल में वे उन ताकतों के मददगार बन चुके हैं जो धर्म के आधार पर लोगों पर हमले करती हैं।

ये अमृतकाल नहीं, सनातनियों का संकटकाल: अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार और केंद्र की नीतियों पर जमकर निशाना साधा. अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को क्रूसौदागरक्र करार देते हुए आरोप लगाया कि वे

मुनाफे के लिए देश की बुनियादी संपत्तियों को बेच रहे हैं. उन्होंने दादरी रैली के बाद सरकार के क्रहोश उड़नेक्र का दावा किया और कहा कि वर्तमान समय अमृतकाल नहीं बल्कि सनातनियों के लिए संकटकाल है. सपा अध्यक्ष ने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) को एकजुट कर बूथ स्तर पर काम करने और आगामी चुनाव में भाजपा को हराकर समाजवादी सरकार बनाने का संकल्प दोहराया. अखिलेश यादव ने प्रदेश की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है और इंसानों के लिए जानवरों वाले इंजेक्शन खरीदे जा रहे हैं. शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया है।

एआईएमआईएम ने बंगाल चुनाव के लिए जारी की पहली लिस्ट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. नामांकन के बीच अब असदुद्दीन ओवैसी अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. ओवैसी पार्टी की पहली लिस्ट में

12 उम्मीदवारों के नाम हैं. एआईएमआईएम ने मोथाबाड़ी से एडवोकेट मोहम्मद मुस्तहिद हक, सुजापुर से रेजाउल करीम और कांडी से मिस्बाहुल इस्लाम खान को टिकट दिया है. रघुनाथगंज से इमरान सोलंकी, आसनसोल से दानिश अजीज, मुरारई से तासीर शेख और नलहाटी से हाजी अंसार शेख साहब चुनाव लड़ेंगे. बारासात से मोनैम सरदार और करणदिघी से महबूब आलम एआईएमआईएम उम्मीदवार होंग। ओवैसी की पार्टी ने सूती में असदुल एसके, बशीरहाट में शबाना परवीन, हावड़ा में असिक राज मंडल पर दांव लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में हुमायूं कबीर की अगुवाई वाली आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी है।

हरीश रावत के बयान से कांग्रेस में घमासान

नईदिल्ली। उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर इन दिनों जो कुछ चल रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि पार्टी के बड़े नेताओं के बीच सियासी पारा एकदम हाई हो गया है। सारा बवाल शुरू हुआ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें उन्होंने क्राजनीतिक व्रतक्र पर जाने का इशारा कर दिया. दरअसल, चर्चा है कि

पार्टी में कुछ नई जॉइनिंग हुई, लेकिन रावत के करीबी संजय नेगी की एंट्री नहीं हो पाई. बस, इसी बात से नाराज होकर उन्होंने राजनीति से दूरी बनाने या क्मौन व्रतक्र जैसा संकेत दे दिया, जिसने पूरी कांग्रेस में हलचल मचा दी. जैसे ही हरीश रावत का यह बयान आया, पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता और चुनाव समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत मैदान में उतर आए। उन्होंने बिना नाम लिए एक बड़ा बयान दे दिया कि किसी को भी यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि पार्टी किसी एक इंसान के बिना नहीं चल सकती. उनका यह कहना मानो जलती आग में घी डालने जैसा था. इसके बाद तो बयानों की ऐसी बौछार हुई कि पार्टी की अंदरूनी कलह सड़क पर आ गई।

पश्चिम बंगाल बढ़ती अराजकता: लोकतंत्र के लिए चुनौती

ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल, जो कभी सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिकता और राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था, आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें लगातार कमजोर होती प्रतीत हो रही हैं। जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य में हिंसा, अराजकता अलोकतांत्रिकता और राजनीतिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घटते सम्मान और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का भी द्योतक है। हाल ही में मालदा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अर्थात एसएआर को लेकर जिस प्रकार का असंतोष और तनाव देखने को मिला, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। मतदाता सूची में नाम जुड़ना या हटना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके लिए स्पष्ट नियम और प्रावधान होते हैं। यदि इस प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा या प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी। एसएआर प्रक्रिया में बाधक बनते हुए जिसे तरह से न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटना सामने आयी है, वह न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतंत्र के लिये एक गंभीर चेतावनी भी है। यह उस व्यापक घातक एवं विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र को भी राजनीतिक दबाव और भीड़तंत्र के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विशेष रूप से यह तथ्य कि बंधक बनाए गए अधिकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं, इस घटना को और अधिक गंभीर बना देता है। यह न केवल कानून के शासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में नक्सल आंदोलन के दौरान हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था, उसने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद वामपंथी शासन के लंबे कालखंड में भी राजनीतिक विरोधियों के प्रति असहिष्णुता और हिंसा की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहीं। सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस एवं ममता बनर्जी के शासन में यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि नए स्वरूप में सामने आई। यह स्पष्ट संकेत है कि समस्या केवल किसी एक दल या विचारधारा की नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र में व्याप्त एक गहरे संकट की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चुनावों के निकट आते ही जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, वे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्य में लगे अधिकारियों को बंधक बनाना यह दर्शाता है कि कुछ तत्व चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मतदाता की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार पर सीधा हमला है।

इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता उल्लेखनीय है। समय-समय पर न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद दिलाई है। किंतु यह भी एक चिंताजनक तथ्य है कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाई देता। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य प्रशासन एवं सत्तारूढ़ पार्टी इन निर्देशों को लागू करने में अक्षम है या इच्छुक नहीं है? यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चुनाव के समय बढ़ती अराजकता के पीछे राजनीतिक बौखलाहट भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। जब किसी दल को अपनी लोकप्रियता में गिरावट का भय होता है, तो वह अक्सर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को दरकिनार कर असंवैधानिक उपायों का सहारा लेने लगता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, जहां सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं पर विपक्ष को डराने, प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं।

सोडा–गन्ना जूस की बर्फ में मिला मरा मेंढक

■ शॉप में बर्फ तोड़ते समय दिखा; कोरबा चौपाटी-संघ ने की फैक्ट्री पर कार्रवाई की मांग

कोरबा कोरबा में सोडा–गन्ना जूस की दुकान में इस्तेमाल की जा रही बर्फ में मरा हुआ मेंढक मिला। जूस बनाते समय जब बर्फ को तोड़ा जा रहा था, तभी उसमें मेंढक दिखाई दिया, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए।

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में चौपाटी संघ ने खाद्य–औषधि विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि विभाग ने मामले में जांच का आश्वसन दिया है।हालांकि इस घटना के बाद दुकान नियमित रूप से संचालित है। मामला शहर के घंटाघर चौपाटी का है। दरअसल, संचालक घंटाघर चौपाटी में अपनी दुकान लगाता है और सोडा–जूस बेचता है।

शुक्रवार शाम दुकान पर कुछ ग्राहक आए और उन्होंने जूस का ऑर्डर दिया। संचालक ने पहले जूस बनाया, बाद में उसमें डालने के बर्फ तोड़ने लगा। इस दौरान बर्फ में मरा हुआ मेंढक मिला। कुछ देर बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। चौपाटी संघ के अध्यक्ष रवि वर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बर्फ तोड़कर मेंढक को बाहर निकला।

हालांकि कुछ देर बाद स्थिति सामान्य हो गई। बताया जा रहा है कि दुकान में इस्तेमाल की जा रही बर्फ धन्नु बर्फ डिपो से लाई गई थी। इस घटना के बाद ग्राहकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि इस तरह की लापरवाही बेहद खतरनाक है। ग्राहकों ने खाद्य विभाग और नगर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।चौपाटी संघ के अध्यक्ष रवि वर्मा ने बताया कि यह घटना एक जूस सेंटर में हुई है। जानकारी के अनुसार, जूस सेंटर संचालक ने निहारिका क्षेत्र की एक दुकान से बर्फ खरीदी थी, जो थोक में फैक्ट्री से लाई गई थी। उन्होंने बर्फ फैक्ट्री के संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं, बर्फ दुकान के संचालक डी. गुप्ता ने बताया कि वे सुभाष चौक पर बर्फ का डिपो चलाते हैं और कई फैक्ट्रियों से बर्फ खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि जिस बर्फ में मेंढक मिला है, वह किस फैक्ट्री से आई थी।

साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह बर्फ उनके डिपो की थी या नहीं। खाद्य–औषधि विभाग के अधिकारी विकास भगत ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जाएगी।

महिला की एडिट की गई अश्लील फोटो वायरल करने की दी धमकी, आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। दुर्ग जिला पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर एक महिला की तस्वीरों से छेड़छाड़ की और उसे सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी थी। इस मामले में उतई पुलिस ने पीड़िता की शिकायत दर्ज कर आरोपी को दबोचा।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम पर एक फर्जी आईडी से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली थी। इसे स्वीकार करने के बाद आरोपी ने उससे बातचीत शुरू की। जिसके बाद सोशल मीडिया से फोटो लेकर आपत्तिजनक तरीके से एडिट करता था। आरोपी ने बाद में व्हाट्सएप पर पीड़िता से संपर्क किया और उसे अश्लील तस्वीरें भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी ने पीड़िता की तस्वीरों को वायरल करने की धमकी दी।आरोपी ने धमकी दी थी कि यदि उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं। तो वह तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। पुलिस ने इस मामले में आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, विशेषकर कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और सोशल मीडिया ट्रैकिंग की मदद से आरोपी की पहचान की। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के बाद आरोपी को बालोद जिले के ग्राम कोहगाटोला से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने घटना को स्वीकार किया। आरोपी ने तीन अलग–अलग फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर यह अपराध किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और चैटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण स्क्रीनशॉट जब्त कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया।

पंडरिया विधानसभा के लोगों को रायपुर में मिलेगी आवास और भोजन की सुविधा, सेवा सदन का शुभारंभ

कबीरधाम। जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक भावना बोहरा ने अपने विधानसभा के लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी पहल के तहत राजधानी रायपुर में पंडरिया सेवा सदन का शुभारंभ किया गया है। यह सेवा सदन खास तौर पर उन मरीजों के परिजनों के लिए तैयार किया गया है, जो इलाज के लिए दूर–दराज से रायपुर आते हैं और उन्हें ठहरने व भोजन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानी झेलनी पड़ती थी।

भावना बोहरा ने बताया कि इस सेवा सदन का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। यहां आने वाले मरीजों के परिजनों को नि:शुल्क ठहरने की सुविधा, शुद्ध एवं सात्विक भोजन, स्वच्छ कमरे, स्नान–शौचालय, पर्याप्त पानी और रात्रि विश्राम के लिए बिस्तर जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दी जाएंगी। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर सेक्टर–2 में स्थित यह सेवा सदन पंडरिया विधानसभा लोगों को सुविधा प्रदान करे। इसे केवल एक भवन नहीं, बल्कि अपना घर बताया जा रहा है, जहां दूर से आने वाले परिवारों को अपनापन और सहूलियत दोनों मिलेंगे।

तेंदुए की 2 खाल के साथ 9 आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर। वन विभाग की टीम ने अंतरराज्यीय वन्यजीव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से तेंदुए की 2 खाल बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार, वन मंत्री के निर्देश एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वन अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो मध्य क्षेत्र भोपाल, राज्य उड़नदस्ता रायपुर और वनमंडल बलरामपुर की संयुक्त टीम ने 2 अप्रैल 2026 को मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। टीम ने थाना बसंतपुर क्षेत्र के ग्राम जमई मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की। तलाशी के दौरान उनके पास से तेन्दुआ की एक खाल बरामद हुई। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया, जिनके पास से एक और खाल जब्त की गई।

बस्तर परिवहन संघ चुनाव में सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान

जगदलपुर। बस्तर परिवहन संघ चुनाव 2026 में इस बार एकता पैनल और अपना पैनल के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। शनिवार सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाता उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं।

चुनाव स्थल पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। दोनों ही पैनलों के समर्थक अपने–अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इस बार मतदान प्रतिशत अधिक रहने की संभावना जताई जा रही है, जिससे चुनाव परिणाम और भी रोचक हो सकता है।

दोनों पैनलों के प्रमुख उम्मीदवारों ने अपनी–अपनी जीत का दावा किया है। अब सभी की नजरें मतदान समाप्ति के बाद होने वाली मतगणना और परिणामों पर टिकी हुई हैं, जो तय करेंगे कि इस बार सबसे बड़े परिवहन संघ की कमान किस पैनल के हाथों में जाएगी। मतगणना के बाद परिणाम देर रात तक आने की संभावना है।

नगर पालिका सीएमओ ने लांघी शालीनता की सीमा, पार्षद से अभद्र भाषा में की बातचीत

बलरामपुर। बलरामपुर नगरपालिका में इन दिनों सियासी और प्रशासनिक टकराव खुलकर सामने आ गया है। पार्षद ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (ष्टरूह्र) प्रवण राय के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक कथित कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की है, जिसमें अभद्र भाषा और धमकी देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने जिले की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

बलरामपुर नगरपालिका के एक भाजपा पार्षद ने ष्टरूह्र प्रणव राय पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों से अभद्र व्यवहार करते हैं, और दबाव की भाषा में बात करते हैं। पार्षद द्वारा वायरल की गई कॉल रिकॉर्डिंग में कथित रूप से धमकी और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल सुनाई दे रहा है।वार्ड 14 पार्षद गौतम सिंह का कहना है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। वे पहले भी कई बार ष्टरूह्र के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज पार्षदों का कहना है कि अपने ही सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही और अधिकारी मनमानी पर उतारू हैं। वहीं, इस पूरे मामले में ष्टरूह्र राय ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वायरल ऑडियो उनका नहीं है, बल्कि-्र तकनीक के जरिए उसमें छेड़छाड़ (टेंपरिंग) की गई है। ष्टरूह्र ने स्पष्ट किया कि वे केवल नियमों के तहत काम करते हैं और किसी भी प्रकार के अवैध दबाव में आकर कार्य नहीं करेंगे। सीएमओ के मुताबिक, कुछ लोग गलत तरीके से काम करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसे वे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य केवल नगर का विकास है।

अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और भाजपा पार्षद कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। एक तरफ वायरल ऑडियो से उठे सवाल हैं, तो दूसरी ओर-्र टेंपरिंग का दावा—ऐसे में सच्चाई क्या है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल, यह विवाद सुशासन के दावों के बीच प्रशासनिक कार्यशैली पर बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहा है।

सांसद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार

दुर्ग। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से सांसद विजय बघेल के खिलाफ आपत्तिजनक इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करने और अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को पाटन पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, गौरव वर्मा ग्राम पूंढा निवासी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो अपलोड की। जिसमें उसने सांसद विजय बघेल और रायपुर एम्स की प्रबंधन व्यवस्था को लेकर बेहद आपत्तिजनक और गाली–गलौज वाली भाषा का उपयोग किया था। वीडियो में युवक ने एम्स में ओपीडी और इलाज की सुविधाओं पर सवाल उठाते हुए सांसद के प्रति व्यक्तिगत और अमर्यादित टिप्पणियां की। मामला सामने आते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की। और आरोपी की पहचान गौरव वर्मा के रूप में होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 353 (2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कोरबा से चलने वाली ट्रेन रिस्टोर, कई ट्रेनें पटरी पर लौटी

कोरबा। पड़ोसी जिले के अकलतरा रेलवे स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए रेलवे ने 12 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को 3 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक रद्द करने की घोषणा की थी। लेकिन अब उन ट्रेनों को रिस्टोर करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए ट्रेनें रद्द नहीं होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार रायगढ़, कोरबा, गेवरारोड सहित अन्य ट्रेनों अपने निर्धारित समय पर चलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल अंतर्गत अकलतरा स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए किए जा रहे नॉन–इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 12 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था। फिलहाल नॉन–इंटरलॉकिंग काम से रेलवे के सामान्य परिचालन में कोई असर नहीं पड़ने की जानकारी दी गई है। इसके बाद किसी भी ट्रेन को निरस्त नहीं करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

रुमाल में पत्थर-प्लास्टिक की चूड़ियां थमाकर फरार हुए ठग

दुर्ग-भिलाई। दुर्ग के व्यस्त हटरी बाजार इलाके में ठगों ने बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया है। ठगों ने झांसा देकर करीब 1.50 लाख के सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। आरोपियों ने महिला को कागज की गड्डी दिखाकर बातों में उलझाया और असली जेवर लेकर भाग निकले। कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बालोद जिले के डौंडी की रहने वाली लक्ष्मी जैन (68) मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे दुर्ग के हटरी बाजार स्थित प्रदीप ग्रीन स्टोर के पास थी। इसी दौरान एक महिला और दो पुरुष उनके पास पहुंचे। ठगों ने नोटों के बंडल दिखाकर बातों में उलझाया। पास से देखने पर वे नोट नहीं, कागज की गड्डियां निकलीं। ठगों ने लक्ष्मी जैन से पहने हुए जेवर दिखाने को कहा। महिला उनके झांसे में आ गईं। उन्होंने सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, चूड़ियां उतारकर दे दी। ठगों ने कपड़े में बांधने का नाटक किया और चालाकी से जेवर बदल दिए। इसके बाद सुरक्षित घर जाने का भरोसा देकर ई–रिक्शा में बैठा दिया। कुछ दूर जाने के बाद महिला ने पोटली खोली।

कोल इंडिया चेयरमैन बी साईंराम एसईसीएल पहुंच

कोरबा। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बी. साईंराम अपने तीन दिवसीय दौरे पर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) पहुंचे। दौरे के पहले चरण में वे रायपुर एयरपोर्ट से सीधे गेवरा हाउस गए, जिसके बाद उन्होंने कुसमुंडा मेगाप्रोजेक्ट का दौरा किया। इस दौरान एसईसीएल के सीएमडी हरिश दुहन उनके साथ मौजूद रहे। चेयरमैन ने नीलकंठ साकार व्यू पॉइंट से खदान का अवलोकन किया। उन्होंने माइन प्लान, चालू वित्त वर्ष के उत्पादन लक्ष्य, मूल्यांकन रणनीति और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने एनआईएमएल पैच का दौरा कर खनन गतिविधियों का निरीक्षण किया। उन्होंने एफएमसी सिस्टम, साइलो के उपयोग, डिस्पैच प्रक्रिया और भविष्य की निकासी योजनाओं की समीक्षा की। कुसमुंडा व्यू पॉइंट पर भी उन्होंने समग्र परिचालन परिदृश्य का आकलन किया।एसईसीएल के कुसमुंडा क्षेत्र के दौरे के दौरान, चेयरमैन बी. साईंराम ने अलग–अलग विभागों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया।

नारायणपुर के जनसेवा अभेद आश्रम में शिविर 12 अप्रैल को

नारायणपुर। जिले के ग्राम नारायणपुर स्थित जनसेवा अभेद आश्रम में अघोर परिषद ट्रस्ट एवं बाबा भगवान राम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में स्थापना दिवस के अवसर पर 12 अप्रैल को नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। शिविर में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के अनुभवी चिकित्सकों की टीम अपनी सेवाएं देगी। मरीजों को एलोपैथिक, होम्योपैथिक सहित अन्य पद्धतियों के विशेषज्ञों द्वारा जांच, परामर्श एवं उपचार की सुविधा एक ही स्थान पर नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। आयोजकों के अनुसार, शिविर में सामान्य से लेकर जटिल बीमारियों का परीक्षण किया जाएगा। मरीजों को उनकी बीमारी के अनुसार आवश्यक सलाह दी जाएगी और आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क दवाइयों का वितरण किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और लोगों को स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक करना है।

अंधेरी रात में जीवनदूत बने सीआरपीएफ जवान

बीजापुर। तिमीनार में 03 अप्रैल 2026 की अंधेरी रात को सीआरपीएफ 165 बटालियन की चार्ली कंपनी ने साहस, संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा का अद्भुत परिचय देते हुए मलेरिया से पीड़ित 3 माह की मासूम बच्ची की जान बचाई। तिमीनार गांव के स्कूल पारा से बच्ची की तबीयत अत्यंत खराब होने की सूचना मिलते ही जवानों ने बिना समय गंवाए तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। गांव तक पहुंचने का रास्ता भी लंबा, उबड़–खाबड़ और अंधेरे में और अधिक खतरनाक हो जाता है। इन सभी जोखिमों के बावजूद सीआरपीएफ के जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए रात के अंधेरे में गांव की ओर कूच किया और कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए समय पर मौके पर पहुंचे। जवानों ने स्कूल पारा, तिमीनार में पहुंचकर बीमार बच्ची को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया। बच्ची की स्थिति गंभीर होने के कारण मौके पर ही प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) उपलब्ध कराया गया, ताकि उसकी हालत और न बिगड़े।

जेईई परीक्षा में नकल के लिए लगाया शातिर दिमाग

चप्पल में मोबाइल छिपाकर लाया था परीक्षार्थी, फिर ऐसे पकड़ा गया

दुर्ग। दुर्ग के पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने एनटीए जेईई मेन के एक्जाम में नकल करने वाले एक परीक्षार्थी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। 2 अप्रैल को पार्थिवी इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षार्थी से एग्जाम में मोबाइल पकड़े जाने पर शिकायत के आधार पर पुलिस ने परीक्षार्थी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

शिकायत दर्ज कराई कि पार्थिवी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेज में 2 अप्रैल को एनटीए जेईई मेन की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दौरान परीक्षार्थी आदित्य कुमार के पास बायोब्रेक के बाद उसकी चप्पल में मोबाइल फोन अनुचित साधन के रूप मे चेकिंग के दौरान पाया गया।

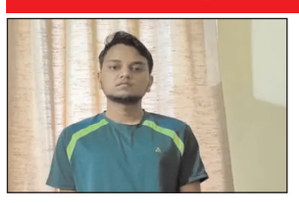

जिसकी लिखित शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस नकल करने वाले परीक्षार्थी आदित्य कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में जुट गई है।

पार्थिवी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेज में एनटीए जेईई मेन की परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसमें प्रथम पाली में एक परीक्षार्थी आदित्य कुमार के पास परीक्षा के दौरान बायो–ब्रेक के बाद उसकी चप्पल में मोबाइल पाया गया। परीक्षार्थी की जब एंट्री तब सिक्योरिटी गार्ड द्वारा ने उसकी मेटल डिटेक्टर से जांच की। परीक्षार्थी ने अपनी जांच से पहले ही अपनी चप्पल उतार दी थी और फिर उसकी जांच की गई थी। जिसके बाद वहां कॉलेज के लेब 12ए सेकेंड फ्लोर में परीक्षार्थी का एग्जाम देने गया। जहां वॉशरूम के लिए बाहर निकला। वॉशरूम से आने के बाद उसकी फिर से सिक्योरिटी गार्ड द्वारा मेटल डिटेक्टर से जांच की। लेकिन फिर से परीक्षार्थी ने अपनी चप्पल जांच से पहले ही निकाल दी और फिर उसने अपनी जांच कराई। जब वह अपनी वॉशरूम से अपनी लैब की ओर वापस जा रहा था। तब सिक्योरिटी गार्ड को उसकी चलने के तरीके से शक हुआ। परीक्षार्थी अपनी चप्पल को घसीट हुए चल रहा था। तब सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी चप्पल की जांच की गई। जांच के दौरान चप्पल के अंदर मोबाइल फोन छुपाया हुआ मिला। इसकी जानकारी सिक्योरिटी गार्ड ने कॉलेज प्रबंधन को दी। जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने कॉलेज प्रबंधन की शिकायत पर परीक्षार्थी आदित्य कुमार के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में जुटी है।

कुत्तों की नसबंदी के लिए विशेष अभियान 10 अप्रैल से

जगदलपुर। नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को नियंत्रित करने के लिए निगम प्रशासन द्वारा कुत्तों की नसबंदी के लिए विशेष अभियान 10 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। इसके लिए चंडीगढ़ की स्नेह एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो नगर निगम के सहयोग से इस अभियान को अंजाम देगी।

नगर निगम क्षेत्र में बीते कुछ समय से आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में कुत्तों के झुंड राहगीरों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इसे देखते हुए निगम ने एनीमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) योजना के तहत यह अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।

नगर निगम आयुक्त प्रवीण वर्मा ने बताया कि इस एजेंसी को काम शुरू करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। यह काम 10 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। इस अभियान के लिए नगर निगम ने कंगोली के डंपिंग यार्ड के पास विशेष व्यवस्था की है, जहां नसबंदी का पूरा कार्य किया जाएगा। एजेंसी के विशेषज्ञों और नगर निगम के कर्मचारियों की संयुक्त टीम इस काम को अंजाम देगी। कुत्तों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर सेंटर लाया जाएगा।

जहां उनका ऑपरेशन कर उन्हें कुछ समय तक निगरानी में रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। निगम आयुक्त प्रवीण वर्मा ने बताया कि एजेंसी का चयन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। इस काम को बिना किसी गतिरोध के पूरा करने के लिए हर स्तर पर तैयारी की गई है। नगर निगम के अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।

नगर निगम के एमआईसी सदस्य लक्ष्मण झा ने कहा कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो रहा है। कई मामलों में कुत्तों के काटने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में नसबंदी ही एक स्थायी समाधान माना जा रहा है, जिससे उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सकेगा और भविष्य में समस्या नहीं बढ़ेगी। राज्य सरकार इस योजना से लोगों को इसका फायदा मिलेगा।

संक्षिप्त समाचार

मंत्री राजवाड़े ने 13.22 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का किया शुभारंभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने भटगांव विधानसभा क्षेत्र के ओड़गी और भैयाथान विकासखंड में 13.22 करोड़ रूपये से अधिक लागत के तीन अहम विकास कार्यों का विधिवत पूजा-अर्चना कर शुभारंभ किया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने विकासखंड ओड़गी के ग्राम हरिहरपुर (छतरंग रोड) में कागज नाला पर 419.37 लाख रूपये की लागत से बनने वाले पुल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में सीधा सकारात्मक परिवर्तन आएगा और भटगांव क्षेत्र विकास की नई दिशा में अग्रसर होगा। श्रीमती राजवाड़े ने भैयाथान विकासखंड के ग्राम सांवरावा में 136.23 लाख रूपये की लागत से जलाशय जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया । उन्होंने प्रतापपुरङ्कभैयाथान मुख्य मार्ग से परसापारा तक लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन किया, जिसकी लागत 766.37 लाख रूपये है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में सड़क, पुल और जल संरचना का सुदृढ़ीकरण होगा, जिससे न केवल आवागमन आसान होगा बल्कि कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

तीन दिग्गजों की रणनीति ने छत्तीसगढ़ को दिलाई नक्सलवाद से मुक्ति

रायपुर। छह दशकों तक भारत की आंतरिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था और विकास यात्रा को चुनौती देता रहा नक्सलवाद आज अपने निर्णायक अवसान की अवस्था में पहुंच चुका है। यह केवल एक सुरक्षा सफलता नहीं, बल्कि उस राष्ट्रीय संकल्प की विजय है, जिसमें स्पष्ट नीति,

अटूट राजनीतिक इच्छाशक्ति और केंद्र-राज्य के अभूतपूर्व समन्वय ने मिलकर एक जटिल और दीर्घकालिक समस्या का समाधान किया है। ये बातें छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहीं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद का यह अवसान इस सत्य को पुनः स्थापित करता है कि भारत में बंदूक की शक्ति अंततः लोकतंत्र की सामूहिक शक्ति के आगे टिक नहीं सकती। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया। इसके पीछे दशकों का संघर्ष, अनगिनत बलिदान और एक ऐसी रणनीतिक निरंतरता रही है, जिसने अंततः इस चुनौती को निर्णायक रूप से परास्त किया। इस ऐतिहासिक क्षण पर मैं उन सभी वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और स्थानीय सुरक्षाबलों के उन रणबाँकुरों को, जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान से इस संघर्ष को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया। यह विजय उनके अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण की अमिट गाथा है।

शराब दुकान के पास तलवार लहराकर लोगों को धमकाने वाला रवि गिरफ्तार

रायपुर। शराब दुकान के पास शराब पिलाओ, नहीं तो जान से मार दूंगा कहकर लोगों को डराने व धमकाने वाले आरोपी रवि वर्मा को धरसींवा पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से धारदार लोहे की तलवार बरामद किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुरा स्थित देशी शराब दुकान के पास एक युवक हाथ में तलवार लेकर हवा में लहरा रहा है और वहां आने-जाने वाले लोगों को शराब पिलाओ, नहीं तो जान से मार दूंगा कहकर धमका रहा है। इससे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया था। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम रवि वर्मा (25 वर्ष), निवासी गणेश नगर कुंरा, वार्ड क्रमांक 11, थाना धरसींवा, जिला रायपुर बताया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक धारदार लोहे की तलवार बरामद की, जिसमें प्लास्टिक का मूठ लगा हुआ था। आरोपी के खिलाफ थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 176/2026 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

खनिज राजस्व में 14 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि वर्ष 2025-26 में 16,625 करोड़ की प्राप्ति

पारदर्शी प्रबंधन और तकनीकी नवाचार से हासिल हुई सफलता

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और सुदृढ़ प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है।

खनिज विभाग के सचिव श्री पी दयानंद ने बताया कि छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16,625 करोड़ का खनिज राजस्व अर्जित कर लक्ष्य का 98 प्रतिशत प्राप्त किया है, जो सुशासन, प्रभावी नीति क्रियान्वयन और मजबूत निगरानी व्यवस्था का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह उपलब्धि न केवल प्रभावी प्रशासनिक रणनीति का परिणाम है, बल्कि राज्य की खनिज आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूती को भी दर्शाती है। इस वर्ष खनिज राजस्व में 14 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले पांच वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर (ष्टत्रक्र) 6 प्रतिशत से दोगुनी से अधिक है। यह वृद्धि राज्य शासन द्वारा अपनाए गए सुधारात्मक और तकनीकी उपायों की सफलता को रेखांकित करती है।

खनिज राजस्व में इस वृद्धि के प्रमुख कारकों में एनएमडीसी तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए डिस्पैच रूट्स का प्रभावी अनुकूलन शामिल है। इसके साथ ही, 'खनिज 2.0' (चद्धड्डह्लद्घ 2.0) जैसे आईटी-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता, निगरानी और संचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार का विशेष ध्यान गौण खनिजों को भी 'खनिज 2.0' प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर रहेगा, जिससे संपूर्ण खनन प्रणाली को डिजिटल और एकीकृत बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, खनिज परिवहन की निगरानी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए वीटीएस (ङ्कञ्जस्र), आई-चेक गेट्स (द्बष्द्धद्गष्य त्नड्डह्लद्गह्य) तथा ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली को और व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य खनिज संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राजस्व में सतत वृद्धि करना है। इन प्रयासों से न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि विकास कार्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।

-विष्णु देव साय,
मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

डॉल्फिन ज्वेलो अपार्टमेंट की लिफ्ट में लगी आग

रायपुर। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र स्थित डॉल्फिन ज्वेलो अपार्टमेंट में शनिवार को अचानक आग लग गई। यह आग अपार्टमेंट की लिफ्ट में लगी। जिससे धुआं तेजी से पूरे परिसर में फैल गया। घटना के समय कई लोग अपने घरों में मौजूद थे। लेकिन समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं, भनपुरी स्थित तंबाखू गोदाम में आग लग गई। कचड़ा जलाने की वजह से कई सालों से बंद गोदाम में आग भड़क उठी। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, डॉल्फिन ज्वेलो अपार्टमेंट के लिफ्ट से पहले धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद कुछ ही देर में आग भड़क उठी। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए कॉलोनीवासियों को अलर्ट किया और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। गार्ड और रहवासियों ने मिलकर फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग काफी हद तक नियंत्रित की जा चुकी थी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि लिफ्ट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। घटना के बाद अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि, वे अपने भवनों में फायर सेफ्टी उपकरणों की नियमित जांच करवाएं और किसी भी आपात स्थिति में सतर्कता बरतें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

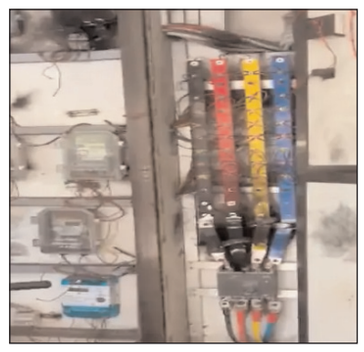

हाईवे पर चाकू दिखाकर लूट की कोशिश नाकाम, पीछा कर आरोपी दबोचा

रायपुर। रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चाकू के दम पर लूट की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना धरसींवा थाना क्षेत्र के ग्राम सांकरा स्थित हाईवे की है, जहां एक युवक ने वाहन चालक को डराकर पैसे लूटने की कोशिश की।

जानकारी के अनुसार, गणेश कुमार चंद्राकर हाईवे किनारे अपनी पिकअप खड़ी कर खाना खा रहे थे। इसी दौरान आरोपी सागर रजक वहां पहुंचा और चाकू दिखाकर उन्हें धमकाने लगा। आरोपी ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे और विरोध करने पर हमला करने की कोशिश की।

इसी बीच गश्त पर निकली पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन टीम ने तुरंत पीछा शुरू किया। अंधेरे के बावजूद करीब 3 किलोमीटर तक पीछा कर आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया गया।

गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से एक बटनदार चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ लूट के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले भी लूट के मामले में जेल जा चुका है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।

अमेरिका-इजरायल-ईरान तनाव के बीच किसानों की मांग

कांग्रेस बोली- श्वेतपत्र जारी करे सरकार

रायपुर। अंतरराष्ट्रीय हालातों और ईरान-इजराइल तनाव के बीच किसानों ने सरकार से खरीफ सीजन से पहले खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने की मांग की है। किसान नेता तेजराम विद्रोही ने कहा कि, सरकार को पहले से पता होता है कि खरीफ सीजन में कितने रकबे में खेती होगी। इसलिए उसी अनुसार खाद का स्टॉक पहले से तैयार रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि, पिछली बार रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान खाद की भारी कमी देखने को मिली थी। जिससे किसानों को परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए सस्ते दर पर और बिना कालाबाजारी के खाद उपलब्ध कराना जरूरी है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि, उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर सरकार केवल बयानबाजी कर रही है, जबकि जमीनी तैयारी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि, पिछले खरीफ सीजन में किसानों को भारी संकट का सामना करना पड़ा था। करीब 4.5 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की जरूरत के मुकाबले शुरुआती दो महीनों में केवल 80 हजार मीट्रिक टन ही उपलब्ध कराया गया था। इससे किसान यूरिया, डीएपी और पोटाश के लिए भटकते रहे। कांग्रेस का कहना है कि, कमी के चलते बिचौलियों ने फायदा उठाया और किसानों को तीन से चार गुना ज्यादा कीमत पर खाद खरीदने को मजबूर होना पड़ा। पार्टी ने आरोप लगाया कि, अगर इस बार भी ऐसी स्थिति बनती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कांग्रेस ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम से स्पष्ट करने को कहा है कि, इस साल उर्वरकों की कुल मांग कितनी है, अब तक कितना स्टॉक तैयार किया गया है ? पार्टी ने कहा कि विपक्ष पर आरोप लगाने के बजाय सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उर्वरकों की उपलब्धता पर पारदर्शिता लाने के लिए श्वेतपत्र जारी करना चाहिए।

रायपुर के नवकार हॉस्पिटल में ससुराल व मायके पक्ष में चले लात-घूंसे

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित नवकार हॉस्पिटल में महिला के इलाज के दौरान उसके मायके और ससुराल पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और धक्का-मुक्की शुरू हो गई।घटना की जानकारी मिलते ही दो थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया। दरअसल महिला फांसी के फंदे पर लटक गई थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इसी दौरान ससुराल और मायके पक्ष के बीच विवाद हो गया। मायके पक्ष ने इसे प्लानिंग के तहत हत्या की कोशिश बताया है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक शिव नगर (संतोषी नगर) निवासी यास्मीन परवीन ने गुरुवार रात अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड की कोशिश की थी। परिजन गंभीर हालत में उसे नवकार हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, जहां उसका इलाज जारी है।

डॉक्टरों के अनुसार महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। शुक्रवार को इलाज के दौरान जब डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि महिला के बचने की संभावना कम है, तब ससुराल पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। इसी दौरान मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद मारपीट में बदल गया। अस्पताल परिसर में कुछ देर तक तनाव का माहौल बना रहा।

घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली और टिकरापारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। एहतियात के तौर पर अस्पताल परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

मामले ने नया मोड़ तब ले लिया, जब मायके पक्ष ने इसे आत्महत्या का प्रयास मानने से इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि यह घटना आत्महत्या नहीं, बल्कि प्लानिंग के तहत हत्या की कोशिश का मामला है, जिसे फांसी का रूप देकर छिपाया जा रहा है।

इस मामले में सिटी कोतवाली टीआई सतीश सिंह ने बताया कि मारपीट की सूचना मिलते ही टीम मौक पर पहुंची थी, दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया गया है। अभी तक किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, अगर शिकायत मिलती है तो मामले की जांच की जाएगी

रायपुर में बिना परमिशन डीजे पर पुलिस की सख्ती, वाहन जब्त

रायपुर। रायपुर में बिना वैध अनुमति डीजे संचालन करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन और उपकरण जब्त कर लिए हैं। यह कार्रवाई पश्चिम ज़ोन के कबीर नगर थाना क्षेत्र में की गई, जहां नियमों का उल्लंघन सामने आया।

पुलिस जांच में पाया गया कि दो संचालकों द्वारा बिना अनुमति डीजे चलाया जा रहा था, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की।

बताया जा रहा है कि इससे पहले पुलिस द्वारा डीजे संचालकों, साउंड सिस्टम और टेंट व्यवसायियों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना अनुमति किसी भी तरह का डीजे संचालन नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी किए जाने पर यह कार्रवाई की गई।

पुलिस ने साफ किया है कि सार्वजनिक शांति भंग करने वाले ऐसे मामलों में आगे भी सख्ती जारी रहेगी और नियम तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बाद सामुदायिक पावर हाउस के रूप में जाने जाएंगे सिद्दी पहलवान

रायपुर। प्रतिभा को किसी परिचय की जरूरत नहीं होती - यह कहावत खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स- 2026 में सच साबित हुई, जहां कर्नाटक के सिद्दी समुदाय के पहलवानों ने मैट पर अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी है। उनकी यह सफलता अब सिर्फ़ पदकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समुदाय के कुश्ती के क्षेत्र में एक ताकत के तौर पर उभरने का प्रतीक है। अफ्रीकी मूल के भारत में लगभग 50,000 सिद्दी लोग रहते हैं, जिनमें से एक-तिहाई कर्नाटक में निवास करते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स-2026 में कर्नाटक के 9 पहलवानों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 4 सिद्दी समुदाय से थे। इन चार पहलवानों में से तीन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया जबकि एक को रजत पदक मिला।

स्वर्ण पदक जीतने वाले पहलवानों में मनीषा जुआवा सिद्दी (76 किग्रा), रोहन एम डोड़ामणि (ग्रीको रोमन 60 किग्रा) और प्रिंसिता पेदरू फर्नांडिस सिद्दी (68 किग्रा) शामिल हैं जबकि शालिना सेयर सिद्दी (57 किग्रा) को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इन पहलवानों की सफलता न सिर्फ उनके संघर्ष और मेहनत की कहानी कहती है, बल्कि कुश्ती जैसे खेलो में सिद्दी समुदाय के बढ़ते वर्चस्व को भी दिखाता है। कर्नाटक के इन चारों पहलवानों का दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ट्रायल हुआ था और वहां भी ये पहले नंबर पर रहे थे। ममता ने कहा, जैसे हमारे देश में कुश्ती में हरियाणा का दबदबा है तो ठीक वैसे ही हमारे राज्य में अहलियाल क्षेत्र का कुश्ती में वर्चस्व रहता है। राज्य में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड डेवलपमेंट एंड सेंटर मुख्य रूप से इन्हीं सिद्दी समुदाय के लिए है। इनके बच्चे यहीं पर ट्रेनिंग करते हैं। पिछले कुछ समय से इस समुदाय के लोगों के अंदर कुश्ती का क्रेज बढ़ा है और वे अब अपने बच्चों को कुश्ती में भेजने लगे हैं। उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ जिले से आने वाले पुरुष पहलवान रोहन एम. डोड़ामणि भी इसी समुदाय से आते हैं। डोड़ामणि की मां सरकारी स्कूल में खाना पकाती हैं जबकि पिता का छह साल पहले ही देहांत हो चुका है। रोहन ने कहा, सिद्दी समुदाय के अंदर समय-समय पर छोटे दंगल होते रहते हैं और जो इनमें जीतता है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया जाता है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स-2026 में स्वर्ण जीतने से पहले मैं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भाग ले चुका हूं। देश में खिलाड़ियों के अंदर छिपी प्रतिभा की पहचान करने और उन्हें एक बेहतर मंच देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और खेल मंत्रालय ने मिलकर 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की थी। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और अब खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की शुरुआत हुई है।

साई के टैलेंट डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य महा सिंह राव कहते हैं, साई और खेल मंत्रालय की तरफ से हम कम उम्र के प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करते हैं ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि 2036 ओलंपिक खेल भारत में हो, उस सपने को साकार करने के लिए ये सरकार की रणनीति का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री के अलावा खेल मंत्री, साई और हम इस सपने को साकार करने में लगे हुए हैं कि आगे आने वाले ओलंपिक खेलों में हम ज्यादा से ज्यादा मेडल जीते। उत्तर कन्नड़ कारवार जिले से आने वाली शालिना सेयर सिद्दी ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के बाद कहा, हमारे समुदाय में कुश्ती को लेकर अब लोग दिलचस्पी लेने लगे हैं। मैंने अपने अंकल के कहने पर कुश्ती शुरू की थी और शुरू से ही वह मुझे ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। मैंने इस प्रतियोगिता के लिए मेहनत तो पूरी की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और मैं स्वर्ण जीतने से चूक गई। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ कारवार जिले से ही आने वाली प्रिंसिता सिद्दी ने कहा, शुरुआत में मुझे कुश्ती में दिलचस्पी नहीं थी और मैं बहुत रोई थी। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब हमारे समुदाय के बच्चे इसमें भाग लेने लगे तो उन्हें देखकर मैं भी प्रैक्टिस करने लगी। यहां तक पहुंचने के लिए मैं शाम-सुबह दो-दो घंटे प्रैक्टिस करती हूं। मुझे इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लाना है और इसके लिए मैं कड़ी मेहनत कर रही हूं। इन पहलवानों की सफलता इस बात को सिद्ध करती है कि जब सही मंच, ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलता है, तो दूरदराज के समुदायों से भी प्रतिभाएं शिखर तक पहुंच सकती हैं और भारत के खेल भविष्य को आकार दे सकती हैं।

ईरान ने सारी दुनिया को बताई अपनी ताकत

सनत जैन

ईरान ने यूएई में स्थापित अमेजॉन का सर्विस डाटा सेंटर चेतावनी देने के दूसरे दिन ही उड़ा दिया। ईरान ने यह हमला ड्रोन से किया था, जो बिल्कुल सटीक था। इसमें कंपनी को काफी नुकसान हुआ। सरवर नष्ट हो जाने के कारण कंपनी की सारी सेवाएं प्रभावित हो गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में घोषणा कर चुके हैं कि वह युद्ध को खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं उसको लेकर ईरान ने काफी आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। जहां-जहां पर अमेरिकी सेवाएं संचालित हो रही हैं वहां-वहां पर ईरान ड्रोन से हमले कर रहा है। ईरान की इस कार्यवाही से सारी दुनिया के देश हैरान हैं। ईरान का शाहिद नामक ड्रोन इस समय चर्चाओं में है। इस ड्रोन को लेकर सारी दुनिया के देशों में जिज्ञासा बनी हुई है। इसने वेब सेंटर में घुसकर जिस तरह से सटीक निशाने पर हमला किया वह आश्चर्यजनक था। ईरान अब खुलकर चेतावनी देकर जिस तरह से हमले कर रहा है उसके सामने अमेरिका और इजरायल का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। सारी दुनिया के देशों में तेल संकट के साथ-साथ अब खाद्य संकट की भी चर्चा हो रही है। करीब 96 देश अभी तेल संकट से जूझ रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं उसमें 125 से अधिक देशों में हार्मोज से जहाजों की आवाजाही में रुकावट से जो संकट पैदा हुआ है उससे अब तेल के साथ-साथ खाद्य संकट भी देखने को मिल रहा है। रही सही कसर जिस तरह से ईरान अमेरिकी कंपनियों पर हमला कर रहा है उससे खाड़ी देशों के साथ-साथ अन्य देशों को भी उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिस तरह के समाचार आ रहे हैं उसमें 100 से अधिक देश अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण बुरी तरह से परेशान हैं। अमेरिका और इजरायल ने अपनी सभी शक्तियों का प्रदर्शन करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। बी-2 बंबर से सेकड़ों स्थानों पर हमला करके ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। अब ईरान खुलकर इसका बदला ले रहा है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल जिस तरह से सटीक निशाना लगाकर खाडी के देशों में अमेरिका और इजरायल के सैन्य ठिकानों के साथ-साथ अब उनके महत्वपूर्ण कारोबार को नष्ट कर रहे हैं इसके कारण सारी दुनिया के देशों में एक नई दहशत फैल गई है। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के संचार माध्यमों को नष्ट किया है तथा जिस तरह से ईरान हमले करके तकनीकी आधार पर अमेरिका और इजरायल को धता बता रहा है उससे सारी दुनिया के देश हैरान हैं। ईरान की तकनीकी जिस तरह से इजरायल और अमेरिका का मुकाबला करते हुए जो ईरानी नवीन प्रयोग हो रहे हैं उससे सबसे ज्यादा परेशानी टेक कंपनियों को हो रही है। उनके सुरक्षित कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करते हुए ईरान द्वारा हमले किए जा रहे हैं, जिसके कारण ईरान का दबदबा बढ़ता चला जा रहा है जिस तरह से ईरान ने अब सरवर और इंटरनेट के जरिए सेवाओं पर निशाना साधना शुरू कर दिया है उसके कारण सभी देशों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। वर्तमान में बैंकिंग एवं अन्य सेवाएं इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ा डाटा सर्वर से जुड़ा हुआ है। यदि उसमें कोई खराबी आती है तो करोड़ों लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। ईरान ने पिछले एक माह में जिस तरह से इस युद्ध को लड़ा है उसने सारी दुनिया के देश हैरानी में हैं। ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइलें अत्याधुनिक संचार माध्यमों से लैस स्थलों को जिस तरह से वह अपने निशाने पर लेकर नुकसान पहुंचा रहे हैं उसने पूरी दुनिया के युद्ध समीकरण को बदल दिया है। तकनीकी क्षेत्र में इजराइल और अमेरिका को चुनौती, ईरान द्वारा दी जा रही है।

जनजातीय खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय गौरव हैं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों और वनांचलों में बच्चे घर के बाहर प्रकृति के सान्निध्य में अधिक समय बिताते हैं। वे खेल-कूद के सहज तरीके खोज लेते हैं। वे मिट्टी में लकीरें खींचकर और आकृतियां बनाकर, खेलने की जगह तैयार कर लेते हैं। वे फलों के सूखे बीजों का खेल की गोटियों की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। सूखे पत्तों, पेड़ों की जड़ों और फटे-पुराने कपड़ों से गेंद बना लेते हैं। बांस का उपयोग कर वे हॉकी और फुटबॉल के गोल पोस्ट बना लेते हैं। इस प्रकार अनेक प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर वे अपने खेल संसार की रचना कर लेते हैं। बहुत से बच्चे बिना जूते और जर्सी के पूरे जोश से खेलते रहते हैं। पोखरों-तालाबों में बच्चे खूब तैरते रहते हैं। तैराकी की इस सहज प्रतिभा को अब उपलब्ध प्रशिक्षण और संसाधनों की सहायता से विकसित कर केवल 15 वर्ष की जाजपुर की बेटी अंजलि मुंडा ने प्रथम 'खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026' में पहले ही दिन तीन स्वर्ण पदक जीत कर पूरे देश के युवाओं को प्रेरित किया।

तीरंदाजी के प्रति जनजातीय लोगों में सहज तरंग-सी होती है। संताल समुदाय ने 1855 में शोषण के विरुद्ध एक घनघोर संग्राम किया था जो 'संताल हूल' के नाम से अमर है। आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना ने उस क्रांति को दबा तो दिया, पर अपने विवरणों में अंग्रेजों ने संताल वीरों के युद्ध कौशल, खासकर तीरंदाजी का विशेष उल्लेख किया है। संताल हूल का नेतृत्व करने वाले बहादुर भाइयों सिदो-कान्हू तथा चांद-भैरव एवं वीरांगना बहनों, फूलो-झानो की प्रतिमाओं का झारखंड में उनके गांव उरी-मारी में जाकर अनावरण करने का सौभाग्य मुझे तब मिला था, जब मैं राज्यपाल थी। तीरंदाजी में एकलव्य की महानता से देश का बच्चा-बच्चा परिचित है। वे श्रेष्ठतम धनुर्धर के रूप में सम्मानित हैं। एकलव्य, सभी देशवासियों के लिए, विशेषकर जनजातीय समाज के लिए एक प्रेरक विभूति हैं। एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालयों में स्थापित 'खेल उत्कृष्टता केंद्र' बच्चों को खेल-कूद की आधुनिक सुविधाओं और पद्धतियों से सक्षम बना रहे हैं।

इसी प्रकार, स्कूल-व्यवस्था के साथ अन्यत्र विद्यमान खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और

उन्हें प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं। मेरे व्यक्तिगत प्रयासों से मेरे गांव में वंचित वर्गों के बच्चों के लिए एक आवासीय स्कूल की स्थापना की गयी है। इस विनम्र प्रयास के तहत स्कूल के परिसर में ही तीरंदाजी के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करायी गयी है। सरकार के प्रयासों के साथ छोटे-छोटे व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास भी जनजातीय बच्चों में निहित खेल प्रतिभाओं को निखारने में सहायक होंगे। मेरे गांव के अन्य जनजातीय बच्चों की तरह मुझमें भी तैराकी सहित व्यायाम और खेलों के प्रति बहुत रुझान था। मैं स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में प्राय: प्रथम स्थान पर रहती थी। एक प्रतियोगिता में जानबूझकर मैंने अपने को पीछे रखा था, ताकि मेरी एक सहेली को प्रथम पुरस्कार का आनंद मिल सके। खेल-कूद से टीम भावना विकसित होती है तथा सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। मैदान पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और मैदान के बाहर गहरी मित्रता खिलाड़ियों में प्राय: देखने को मिलती है।

मेरे भाई फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, जो गंभीर चोट के कारण आगे नहीं खेल सके। मेरे परिवार के कुछ अन्य सदस्यों ने भी विभिन्न खेलों में उत्कृष्टता प्रदर्शित की है। इस निजी विवरण से मैं यह बताना चाहती हूं कि जनजातीय परिवारों में खेल-कूद की जीवंत परंपरा विद्यमान है। उनमें खेलों के लिए असीम प्रतिभा, ऊर्जा और रुचि है तथा आगे बढ़ने का हौसला भी है। सुविधाओं और प्रशिक्षण द्वारा ऐसी प्रतिभाओं को निखारने से, खेल-कूद उनके लिए केवल मनोरंजन और सामाजिक मेल-जोल का जरिया न होकर जीवन में आगे बढ़ने का, आर्थिक आत्मनिर्भरता का और सामाजिक सम्मान प्राप्त करने का माध्यम बन सकता है। इस संदर्भ में 2018 से केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा खेल संस्थानों के साथ मिलकर चलाये जा रहे 'खेलो इंडिया' अभियान द्वारा अच्छा बदलाव आया है।

कुछ वर्षों पहले तक हमारे देश में खेल-कूद की अच्छी सुविधाएं केवल महानगरों तक सीमित थीं, जबकि ग्रामांचलों और वनांचलों में अनेक प्रतिभावान खिलाड़ी रहते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में खेल अकादमी और प्रशिक्षण सुविधाएं सुलभ नहीं होती थीं। अब एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालयों में बच्चों के खेल-कूद पर विशेष ध्यान देने से लेकर 'खेलो इंडिया जनजातीय खेल' जैसे प्रयत्नों के बल पर जनजातीय प्रतिभाओं को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिल रहा है। मुझे याद है कि मेरे विद्यार्थी जीवन के दौरान ग्रामीण स्तर पर पांच-छह गांवों के लोग मिलकर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित किया करते थे। कुछ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं भी जनजातीय क्षेत्रों में खेल-कूद को बढ़ावा देती रही हैं।

प्राय: ग्रामीण क्षेत्र की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अच्छे खिलाड़ी भी ग्रामीण स्तर से ऊपर नहीं उठ पाते थे। पिछले कुछ वर्षों में इस स्थिति को बदलने के अनेक सराहनीय प्रयास किये गये हैं। ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए 'खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026' का आयोजन किया गया। इस आयोजन से जमीनी स्तर के जनजातीय खिलाड़ियों को भी पहचान मिली है तथा उन्हें सुविधाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध कराये गये हैं। इन राष्ट्रीय खेलों में लगभग सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है।

भारत ने खिलाड़ियों की नैसर्गिक प्रतिभा के बल पर ओलिंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक हॉकी के लिए 1928 में जीता था। उस विजय में जनजातीय समुदाय के खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तब से आज तक दिलीप तिर्की, सुबोध लकड़ा और सलीमा टेटे जैसे स्टार हॉकी खिलाड़ी भारत की पुरुष तथा महिला टीमों को जनजातीय प्रतिभा से समृद्ध करते रहे हैं। भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे 'खेलो इंडिया' राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभी भौगोलिक क्षेत्रों, सामाजिक वर्गों और संस्थाओं के लिए समुचित खेल इकोसिस्टम उपलब्ध कराने का समावेशी प्रयास किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत, खेल-कूद में बेटियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए चलायी जा रही 'अस्मिता' नामक योजना से जनजातीय बेटियों की क्षमता भी विकसित हो रही है। 'खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026' द्वारा शुरू की गयी मुहिम को मजबूत बनाते हुए जनजातीय खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से खिलाड़ियों के ऐसे समूह तैयार होंगे, जो विश्व पटल पर भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगे।

पिछले कुछ महीनों में आयोजित बस्तर एवं सरगुजा ओलिंपिक में कुल सात लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। उन खिलाड़ियों में कुछ ऐसे युवा भी थे, जो नक्सलवाद का रास्ता छोड़ खेल-कूद के सन्मार्ग पर चल पड़े हैं। खेल-कूद से युवा ऊर्जा को सकारात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। सरकार द्वारा युवाओं में खेल प्रतिभा को पहचानने और विकसित करने के अच्छे परिणाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दिखाई देने लगे हैं। युवाओं, खासकर जनजातीय युवाओं की खेल प्रतिभा हमारे राष्ट्र की अमूल्य सामाजिक पूंजी है। मुझे विश्वास है कि इस अनमोल संसाधन का सदुपयोग करते हुए हमारा देश खेल-कूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता के अनेक गौरवशाली प्रतिमान स्थापित करेगा। इसी विश्वास के साथ मेरा संदेश है-खेलो इंडिया! खूब खेलो इंडिया!

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

ऋषि तत्काल आ पहुंचे आकारैरिङ्गितैर्गत्या-इस दुराचारपूर्ण काण्ड को देखते ही आग बगूला हो गए इन्द्र को सहस्रभग हो जाने का, और अहल्या को पत्थर की शिला बन जाने का शाप दे डाला। इन्द्र अपने कर्तव्य पालन में कृतकार्य हुवे. अर्थात् गोत्तम ऋषि का चिरसंचित तपोबल - जिससे कि देवसमाज भयभीत हो रहा था, इस शाप के बहाने नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। दूसरे शब्दों में एक खतरनाक व्यक्ति के हाथ से थामे हुये सर्वांतकारी खड्ग को सर्वहित-चिन्तक, परोपकारी ने धैर्यपूर्वक अपने सिर पर गिरवाकर उसे सदा के लिए कुण्ठित बना डाला। इस तरह गोत्तम के तपोबल से त्रस्त हुये अनेक देवताओं का त्राण हुआ, यही इन्द्रकृत अहल्याघर्षण का अभिप्राय है ।

इन्द्र ने विषय-भोग की लालसा से नहीं, बल्कि गोत्तम जी की तपश्चर्या से भयभीत हुवे देववृन्द की संरक्षा के लिए ही अहल्या-घर्षण का अभिनय किया था% हमारे उपयुक्त अभिप्राय को डङ्क की चोट घोषित करने वाले नीचे लिखे प्रमाण दर्शनीय हैं, यथा-

(क) ग्रफलस्तु ततः शक्रो देवानग्निपुरोगमान्।
अब्रवीत्त्रस्तनयनः सिद्धगन्धर्वचारणान् ॥1॥
कुपता तपसो विघ्नं गोत्तमस्य महात्मनः।
क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकार्य्यमिदं कृतम् ।।2।।
अफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात्सा च निराकृता ।
शापमोक्षेण महता तपोस्थापहृतं मया ।।3।।
तन्मां सुरवरास्सर्वे ऋषिसंघाः सचारणाः ।
सुरकार्य्य-करं यूयं सफलं कर्तुमर्हथ ।।4।।
शतक्रतोर्वचः श्रुत्वा देवाः साग्निपुरोगमाः ।
पितृदेवानुपेत्याहुः सर्वे सह मरुद्गणैः ॥5॥
अयं मेषः सवृषणः शक्रो ह्यवृषणः कृतः ।
भेषस्य वृषणौ गृह्य शक्रायाशु प्रयच्छत ।।6।।
अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः ।
उत्पाट्य मेष-वृषणौ सहस्त्राक्षे न्यवेशयन् ।।7।।

क्रमशः ...

बाबू जगजीवन राम

निधि अविनाश

भारत की आजादी के बाद राजनीति में बहुत ही कम नेता ऐसे रहे जिन्होंने न केवल मंत्री बल्कि कई मंत्रालयों की चुनौती को स्वीकार किया और उसे अंतिम अंजाम तक भी पहुंचाया। भारतीय राजनिति शिखर के पुरुष रहे जगजीवन राम को मंत्री के रूप में जो विभाग मिला उन्होंने अपनी ईमानदारी से उसका संचालन किया। जगजीवन राम जो ठान लेते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। वह हर एक चुनौतियों का डटकर सामना करते थे और अन्याय के खिलाफ कभी भी समझौता नहीं किया। दलितों के सम्मान के लिए जगजीवन राम हमेशा संघर्षरत रहे। बाबू जगजीवन राम एक दलित परिवार से आते थे। उनका जन्म 5 अप्रैल, 1908 को बिहार में भोजपुर के चंदवा गांव में हुआ था। जन्म से ही उन्हें बाबूजी के नाम से संबोधित किया जाने लगा। जगजीवन के पिता शोभा राम एक किसान थे और ब्रिटिश सेना में नौकरी करते थे। अपनी पढ़ाई के लिए वह कोलकाता चले गए और वहां से उन्होंने 1913 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसी दौरान उनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी हुई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जगजीवन राम ने आजादी की लड़ाई में भी जमकर भूमिका निभाई। इन कारणों से बापू के वह सबसे खास पात्र भी बने और राजनीति के केंद्र में आए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जगजीवन राम ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और इसी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा।

जगजीवन राम को 1936 में बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया। अगले साल वह बिहार विधानसभा के लिए चुने गए और संसदीय सचिव भी बनाया गया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कामचलाऊ सरकार का गठन किया गया और अनुसूचित जातियों के इकलौते नेता होने के नाते जगजीवन राम को एक नेता के रूप में शामिल किया गया। सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बनने के साथ-साथ उन्होंने श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी बहुत ही सक्रिय रूप से संभाली। इसी समय से जगजीव राम का एक केंद्रीय मंत्री के रूप से सफर शुरू हो गया। 1952 से लेकर 1984 तक लगातार वह एक सांसद के रूप में कार्यरत रहे। नेहरू मंत्रिमंडल, इंदिरा गांधी, जनता सरकार के नेतृत्व में जगजीवन राम एक केंद्रिय मंत्री के रूप में काम करते रहे। अपने इतने लंबे कॅरियर के दौरान उन्हें श्रम, कृषि संचार रेलवे और रक्षा जैसे कई मंत्रालयों में काम करने का मौका मिला। जगजीवन राम को एक भारतीय समाज और राजनीति में दलित वर्ग के मसीहा के रूप में जाना जाता है। वह उन गिने-चुने नेताओं में से एक है जिन्हें राजनीति के साथ-साथ दलित समाज का भला करने के लिए भी याद किया जाता है। लाखों-करोड़ों दलितों की आवाज बनकर जगजीवन ने एक नई जिंदगी लोगों को प्रदान की। राजनीति का हिस्सा रहे जगजीव राम ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में लगा दिया और जुलाई 1986 में 78 साल की उम्र में जगजीवन राम ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

खाड़ी युद्ध का असली ट्रेलर

देवाशिष बसु

ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध पांचवें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और इस ?की चपेट में आकर भारतीय सूचकांक 9 फीसदी से अ?धिक टूट चुके हैं। युद्ध के प्रत्यक्ष प्रभाव हम सभी के सामने हैं क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद हो चुका है। भारत के कुल आयात का लगभग 54 फीसदी कच्चा तेल, 60 फीसदी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और लगभग 90 फीसदी तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं। तेल और गैस के साथ-साथ भारत को नेफ्था, विमान ईंधन (एटीएफ) और गैसऑयल जैसे परिष्कृत उत्पादों की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है।

खाद्य क्षेत्र में स्थिति और भी गंभीर है। खाद्य उत्पादन डीजल और उर्वरकों पर निर्भर करता है। उर्वरक जैसे यूरिया, अमोनिया और फॉस्फेट पैदावार बढ़ाते हैं। वैश्विक यूरिया व्यापार का 30 फीसदी से अधिक और अमोनिया और फॉस्फेट का लगभग 20 फीसदी हिस्सा भी होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है।

खाड़ी क्षेत्र से दुनिया को कुल हीलियम के एक तिहाई से अधिक की आपूर्ति होती है। हीलियम सेमीकंडक्टर और इमेजिंग मशीनों के लिए अत्यंत जरूरी घटक है। पूरी दुनिया में मेथनॉल उत्पादन में भी इसकी लगभग 30 फीसदी हिस्सेदारी है जो प्लास्टिक, पेंट और ईंधन के लिए एक आधारभूत रसायन है। खाड़ी क्षेत्र सल्फर निर्यात में भी अग्रणी है (विश्व के कुल निर्यात का लगभग 45 फीसदी) जिसका इस्तेमाल सीधे उर्वरक उत्पादन में उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल तांबा, कोबाल्ट और निकल के निष्कर्षण में किया जाता है जिनका उपयोग ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में होता है।

इस युद्ध से एल्युमीनियम की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। दुनिया में एल्युमीनियम उत्पादन में खाड़ी क्षेत्र लगभग 9 फीसदी योगदान देता है और चीन के बाहर कुल आपूर्ति में 22 फीसदी दखल रखता है जिससे यूरोप और अमेरिका में वाहन से

लेकर निर्माण क्षेत्रों के लिए जोखिम खड़ा गया है। निवेशकों को अब यह तय करना होगा कि इन प्रभावों का किस हद तक असर मूल्य निर्धारण में दिख चुका है।

विमानन ईंधन किसी विमानन कंपनी के परिचालन लागत में 35-40 फीसदी हिस्सा रखता है। विश्लेषकों के अनुसार ईंधन की कीमतों में 10 फीसदी वृद्धि से परिचालन लाभ लगभग 15 फीसदी तक घट जाता है। पश्चिम एशियाई हवाई क्षेत्र बंद होने और उड़ान मार्गों के लंबा होने से विमानन कंपनियों का मार्जिन और भी कम हो जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में दबाव अधिक व्यापक है। कच्चे तेल से जुड़ी पैकेजिंग सामग्री पॉलिएथिलीन टेरेफ्थालेट (पीईटी) चिप, लिक्विड पैराफिन, उच्च घनत्व पॉलिइथिलीन और लचीले लैमिनेट परिचालन लागत का लगभग 15 फीसदी हिस्सा हैं।

कीमतें नियंत्रित करने की अधिक ताकत रखने वाली कुछ बड़ी कंपनियां बढ़ी लागत का कुछ बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं मगर छोटी एवं असंगठित कंपनियां ऐसा नहीं कर सकतीं जिससे बाजार हिस्सेदारी में बदलाव तेजी से हो रहा है। कांच का उत्पादन प्राकृतिक गैस पर निर्भर करता है। कपड़ा उत्पादक मध्यवर्ती सामग्रियों पर निर्भर हैं। युद्ध के कारण आपूर्ति में आए व्यवधान ने पॉलिएस्टर धागे की कीमतें पहले ही 15-20 फीसदी तक बढ़ गई हैं। सीमेंट प्रत्यक्ष आपूर्ति व्यवधान से बच जाता है मगर फिर भी मूल्य प्रभावों से प्रभावित होता है। ईंधन की लागत में वृद्धि से आय कम हो सकती है, साथ ही पैकेजिंग में उपयोग होने वाले पॉलिप्रोपिलीन की उच्च कीमतों से भी नुकसान होता है। गुजरात के मोरबी में टाइल उत्पादकों ने गैस की कमी के कारण अपना काम बंद कर दिया है।

ये सभी छोटे-छोटे प्रभाव हैं मगर ये सब मिलकर एक ऐसे हालात तैयार कर देते हैं जो समय और कीमतों से प्रभावित होते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से चल रही किल्लत के दौरान बहुत कम गड़बड़ी दिखाई दी है। मगर अगले एक से तीन महीनों में जब भंडार कम हो जाएगा तो इसकी दोबारा आपूर्ति बहुत अधिक लागत पर होगी जिससे एक बड़ा अप्रत्यक्ष झटका लगेगा।

सवाल यह है कि बाजार ने इसका किस हद तक अनुमान लगा लिया है? बाजार सबसे पहले लगने वाले झटके पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं यानी शेयर बाजार लड़खड़ाते हैं, मुद्राएं कमजोर होती हैं आदि। मगर स्वभाव से आशावादी होने के कारण निवेशक यह मान लेते हैं कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। दूसरे और तीसरे स्तर पर होने वाले प्रभाव कम दिखाई देते हैं। व्यापक राजकोषीय गणित और उपभोग पर इसके प्रभाव को तत्काल अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता है।

कच्चे तेल की कीमत में प्रत्येक 10 डॉलर की वृद्धि से भारत की आयात लागत में 12 अरब से 15 अरब डॉलर की वृद्धि होती है। 80 डॉलर से ऊपर तेल की कीमतें रहने से मुद्रास्फीति दर 4.5 फीसदी से ऊपर जाने का खतरा है। इससे चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.5-2 फीसदी तक बढ़ जाएगा और रुपया कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले 95 से भी आगे जा सकता है। रुपया कमजोर होने और विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली के बाद विदेशी निवेश ठिठक जाएगा।

सबसे बड़ा प्रभाव बिगड़ते व्यापार संतुलन, ऊंची मुद्रास्फीति, बढ़ते राजकोषीय घाटे और घटते कर राजस्व के रूप में सामने आएगा। उर्वरकों की बढ़ती लागत से सब्सिडी का आंकड़ा बढ़ जाता है और इसकी (सब्सिडी की) कमी के कारण किसान उर्वरकों का इस्तेमाल करने से कतराने लगते हैं। इससे कुल फसल पैदावार कम रहने का जो ?खिम उत्पन्न हो जाता है। सरकार ईंधन की कीमतों में कुछ वृद्धि सहन कर सकती है मगर ईंधन और उर्वरक दोनों की कीमतों में अचानक वृद्धि से जूझ पाना कठिन है। इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार पूंजीगत व्यय में कटौती करेगी जो हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में अहम रहा है।

अगर युद्ध नहीं रुकता है तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। मुद्रास्फीति बढ़ने से स्थानीय मुद्रा कमजोर होती है जिसका सीधा असर ऊर्जा पर अधिक लागत के रूप में सामने आता है। महंगे ईंधन और उर्वरकों से बढ़ती लागत के कारण परिवारों के पास विवेकाधीन खर्च कम हो जाएगा और कर राजस्व में कमी आएगी। अर्थव्यवस्था शुरुआती कुछ हफ्तों में झटकों को सहन कर सकती है।

इसके अलावा समस्या कई छोटे-छोटे बदलावों के रूप में सामने आएगी यानी मार्जिन में कुछ प्रतिशत अंकों की गिरावट होगी, उत्पादन में कुछ हफ्तों की देरी और मुद्रास्फीति में कुछ आधार अंक की वृद्धि हो जाएगी। बाजार हर बार इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। चूंकि, ये बदलाव धीरे-धीरे होंगे इसलिए उनके प्रभाव का सही अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकेगा। कुल मिलाकर उतार-चढ़ाव भरे सफर के लिए तैयार रहें।

आज का इतिहास

1927 निषेध ब्यूरो संयुक्त राज्य अमेरिका के खजाना विभाग के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया।
1955 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इस्तीफा दिया।
1958 पहले लाइव कनाडाई राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल में से एक, डिस्कवरी पैसेज, ब्रिटिश कोलंबिया में पानी के नीचे स्थित रिपल रॉक, एक योजनाबद्ध विस्फोट में नष्ट हो गया था।
1964 नौसेना ने पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया।
1966 इंडोनेशियाई सेना की मांग, देश संयुक्त राज्य अमेरिका से फिर से जुड़ें।
1971 अपोलो 14, तीसरे अमेरिकी मानवयुक्त चंद्रमा अभियान, फ्रा मौरो एलन शेपर्ड और एडवर्ड मिशेल (अपोलो 14) के पास की भूमि चंद्रमा पर 4 घंटे तक चलती है।
1974 स्टीफन किंग ने अपना पहला उपन्यास कैरी प्रकाशित किया।
1975 सऊदी अरब के राजा फ़ैजल की हत्या हुई।
1991 अंतरिक्ष यान एसटीएस 37 (अटलांटिस 8) का प्रक्षेपण किया गया।
1992 बोस्नियाई युद्ध-अज्ञात बंदूकधारियों ने साराजेवो में युद्ध-विरोधी प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी करते हुए दो लोगों की हत्या कर दी, जो चार साल के सर्जियो की घेराबंदी की शुरुआत थी।
1993 रोल हॉल ऑफ फेम और क्लीवलैंड की चट्टान 1993 में शुरू होती है।
1994 गोल्डन न्यूयॉर्क सिटी में जैकी मेसन पॉलिटिकली गलत ओपन, मिशिगन 77-71 वर्ष 1993 में धड़कता है।
1996 जॉन बॉबिट को 120 दिनों के लिए लास वेगास में नजरबंद रखा गया है।
1998 जापान के आकाशी काइको ब्रिज , अवाजी आइलैंडैंड कोबे को जोड़ने, यातायात के लिए खोला गया, जो 1,991 मीटर (6,532 फीट) की मुख्य अवधि के साथ दुनिया का सबसे लंबा निलंबन पुल बन गया।
1999 इराक में वियाग्रा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा, मलेशिया में हेन्ड्रा नामक वायरस से बचाव के लिए 8 लाख 30 हज़ार सूअरों की सामूहिक हत्या किये जाने का कार्यक्रम प्रारम्भ।
2009 देश संगीत पुरस्कार का 44 वा अकादमी कैरी अंडरवुड और ब्राड पैसले ने जीता।
2010 अमेरिकी राज्य वेस्ट वर्जीनिया के कोयला खदान में विस्फोट से 22 लोगों की मौत हुई।
2011 वर्ष 2011 में इडाहो हाउस ऑफ प्रतिनिधियों में 20 सप्ताह से अधिक पुराने झगड़े के गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल।

पश्चिम बंगाल बढ़ती अराजकता : लोकतंत्र के लिए चुनौती

ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल, जो कभी सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिकता और राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था, आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें लगातार कमजोर होती प्रतीत हो रही हैं। जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य में हिंसा, अराजकता अलोकतांत्रिकता और राजनीतिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घटते सम्मान और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का भी द्योतक है। हाल ही में मालदा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अर्थात एसएआर को लेकर जिस प्रकार का असंतोष और तनाव देखने को मिला, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। मतदाता सूची में नाम जुड़ना या हटना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके लिए स्पष्ट नियम और प्रावधान होते हैं। यदि इस प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा या प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी। एसएआर प्रक्रिया में बाधक बनते हुए जिसे तरह से न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटना सामने आयी है, वह न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतंत्र के लिये एक गंभीर चेतावनी भी है। यह उस व्यापक घातक एवं विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र को भी राजनीतिक दबाव और भीड़तंत्र के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विशेष रूप से यह तथ्य कि बंधक बनाए गए अधिकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं, इस घटना को और अधिक गंभीर बना देता है। यह न केवल कानून के शासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में नक्सल आंदोलन के दौरान हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था, उसने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद वामपंथी शासन के लंबे कालखंड में भी राजनीतिक विरोधियों के प्रति असहिष्णुता और हिंसा की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहीं। सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस एवं ममता बनर्जी के शासन में यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि नए स्वरूप में सामने आई। यह स्पष्ट संकेत है कि समस्या केवल किसी एक दल या विचारधारा की नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र में व्याप्त एक गहरे संकट की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चुनावों के निकट आते ही जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, वे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्य में लगे अधिकारियों को बंधक बनाना यह दर्शाता है कि कुछ तत्व चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मतदाता की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार पर

सीधा हमला है।

इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता उल्लेखनीय है। समय-समय पर न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद दिलाई है। किंतु यह भी एक चिंताजनक तथ्य है कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाई देता। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य प्रशासन एवं सत्तारूढ पार्टी इन निर्देशों को लागू करने में अक्षम है या इच्छुक नहीं है? यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चुनाव के समय बढ़ती अराजकता के पीछे राजनीतिक बौखलाहट भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। जब किसी दल को अपनी लोकप्रियता में गिरावट का भय होता है, तो वह अक्सर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को दरकिनार कर असंवैधानिक उपायों का सहारा लेने लगता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, जहां सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं पर विपक्ष को डराने, प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

नागरिक समाज सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक केवल प्रशासनिक उपायों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कानून का शासन, संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति इन सभी पहलुओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि चुनाव प्रक्रिया ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नहीं रह जाती, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मतदाता का विश्वास होता है, और यदि मतदाता को यह लगने लगे कि मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया या प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता स्वत: कमजोर होने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक नाकामी का प्रश्न भी गंभीरता से सामने आता है। किसी भी राज्य में यदि अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, न्यायिक अधिकारी तक बंधक बना लिए जाते हैं और पुलिस या प्रशासन समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाता, तो यह प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी का स्पष्ट प्रमाण है। प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना और सरकारी कार्यों को निर्भय वातावरण में संपन्न कराना होता है। यदि प्रशासन यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, तो इससे जनता में भय और अविश्वास दोनों बढ़ते हैं। जनता का विश्वास ही किसी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होता है, और जब यही विश्वास डगमगाने लगता है, तो शासन की वैधता पर भी प्रश्नचिह्न लगने लगते हैं।

राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों के संवाहक भी होते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को संयम, कानून के सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कटु संघर्ष में बदल जाती है और कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल चुनाव को युद्ध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्सव के रूप में देखें। आज आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं को केवल एक राज्य की समस्या न मानकर लोकतंत्र के लिए चेतावनी के रूप में देखा जाए। यदि प्रशासनिक तंत्र कमजोर होगा, राजनीतिक दल मर्यादा नहीं रखेंगे, और जनता का विश्वास कम होता जाएगा, तो लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान या न्यायालय नहीं कर सकते, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक निष्पक्षता और जनता की जागरूकताकृतीनों का संतुलन आवश्यक है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थितियां हमें यही संदेश देती हैं कि लोकतंत्र को केवल चुनाव से नहीं, बल्कि व्यवस्था की निष्पक्षता, कानून के शासन और नागरिक विश्वास से मजबूत बनाया जा सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि राज्य सरकार, चुनाव आयोग और न्यायपालिका मिलकर ठोस कदम उठाएं। कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए, दोषियों के खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई हो और प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जाए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें। निश्चित ही यह समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति एक चेतावनी है कि यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह अराजकता और गहराई तक फैल सकती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि हम सभी मिलकर कानून, नैतिकता और सहिष्णुता के मूल्यों को पुन: स्थापित करें। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां से वह या तो लोकतांत्रिक पुनर्जागरण की ओर बढ़ सकता है या अराजकता के गहरे गर्त में गिर सकता है। यह निर्णय न केवल राजनीतिक नेतृत्व, बल्कि पूरे समाज को मिलकर लेना होगा।

सरकारी कर्मियों को बंधक बनाना अनुचित

पवन

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत निर्वाचन नामावलियों के अद्यतन कार्य में लगे सात न्यायिक अधिकारियों, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं, को भीड़ द्वारा नौ घंटे से भी अधिक समय तक बगैर भोजन-पानी के बंधक बनाए रखने की घटना पर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख बिल्कुल जायज है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह जैसी तो प्रतीत होती ही हैं, लोकतंत्र की जड़ों में पैठ बनाते खतरनाक रुझानों की ओर भी संकेत करती हैं।

यह ध्यान देने वाली बात है कि शीर्ष अदालत ने इसे एक सुनियोजित प्रयास करार दिया है, जिसका अर्थ ही है कि यह कोई आकस्मिक या भावनात्मक उबाल नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने की एक गंभीर कोशिश थी। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के लिए सात अप्रैल की समय-सीमा तय की है और 31 मार्च तक कुल साठ लाख में से 47 लाख से भी ज्यादा आपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है। प्रक्रिया से जुड़े आंकड़ों पर खुद सर्वोच्च न्यायालय ने संतुष्टि जताई है, जो इस पर भरोसा जताने के लिए काफी होना चाहिए। फिर भी अगर किसी को एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कोई आपत्ति हो, तो उसे जाहिर करने के रास्ते हैं, पर अधिकारियों को डराना-धमकाना या उन्हें शारीरिक रूप से रोकना न केवल प्रशासनिक कामकाज में विघ्न डालता है, बल्कि मताधिकार की पवित्रता को भी चोट पहुंचाता है। इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका तो और भी

शर्मनाक रही। घेराव शुरू होते ही सर्वोच्च न्यायालय तक सूचना पहुंच गई, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह कहना कितना तर्कसंगत है कि उन्हें किसी ने सूचना नहीं दी।

अदालत ने इसका गंभीर संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत आला अधिकारियों को उचित ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राज्य में यह ऐसी कोई अकेली घटना नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान, पहले भी निर्वाचन अधिकारियों का पीछा करने, उन्हें घेरने या मारपीट करने की घटनाएं सामने आती रही हैं, पर मालदा की घटना ने तो हद ही पार कर दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत का पश्चिम बंगाल को राजनीतिक तौर पर सर्वाधिक ध्रुवीकृत राज्य बताना और चुनाव आयोग की बंगाल में जंगल राज होने की टिप्पणी गंभीर है। ऐसे में, यह जरूरी है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

भाजपा के लिए भस्मासुर साबित होगा चुनाव आयोग?

सनत कुमार जैन

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है विधानसभा चुनाव के लिए एसआईआर की प्रक्रिया पिछले कई माह से चल रही है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई चल रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से आर पार की लड़ाई लड़ रही है उसके कारण वह चुनाव आयोग और भाजपा के लिए एक बड़ा सिर दर्द बन गई हैं। चुनाव आयोग का एसआईआर का खेल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने समझ लिया है फॉर्म नंबर 6 और 7 का जो खेल चुनाव आयोग में चल रहा है उसे भी विपक्षी दलों और ममता बनर्जी ने पहचान लिया है जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बड़े अधिकारियों से लेकर बीएलओ तक के ट्रांसफर किए हैं। हर मामले में ममता बनर्जी और उनके अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया है हाई कोर्ट में भी ममता बनर्जी ने लड़ाई लड़ने में कोई कोताही नहीं बरती निश्चित रूप से चुनाव आयोग को जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है सरकार का संरक्षण प्राप्त है उसको देखते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षाकृत लाभ नहीं मिला इसके बाद भी उन्होंने पूरी तरह से जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं उसमें एक धर्म विशेष के लोगों में जब हाईकोर्ट के जज का नाम कट गया उससे यह मामला जनता के बीच बड़ी तेजी के साथ पहुंच गया हाल ही में न्यायिक अधिकारी ब्लॉक ऑफिस में बैठकर जिन लोगों के नाम नहीं जुड़े थे उनकी शिकायतों पर जांच कर रहे थे उन न्यायिक अधिकारियों को मतदाताओं ने कई घंटे तक बंधक बना कर रखा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पूरी रात जाग कर प्रशासन को सक्रिय करना पड़ा उसके बाद सुनवाई कर रहे जजों को बाहर निकाला गया बाद में सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा कि सीआरपीएफ को न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की ड्यूटी में लगाया जाए इस मामले में पहले ही टीएमसी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए यह कह दिया था जिस बड़े पैमाने पर अधिकारियों के

ट्रांसफर केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बिना राज्य सरकार के परामर्श के किए गए हैं उसके बाद राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेश पर पूरा प्रशासन कम कर रहा है कानून व्यवस्था की पश्चिम बंगाल में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है जिद मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनकी संख्या लाखों में है और वह अपने नाम जुड़वाने के लिए शोध आक्रोषित होकर स्थानीय अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं। हरियाणा महाराष्ट्र तथा बिहार के चुनाव में किस तरह से फॉर्म 6 एवं 7 का दुरुपयोग किया गया है किस तरह से चुनाव में मतदाताओं के नाम जोड़ने और काटने में अंतिम समय पर चुनाव आयोग द्वारा हेराफेरी की गई है इसका खुलासा अब पूरी तरह से हो गया है राहुल गांधी ने जब पत्रकार वार्ता कर चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए थे उस समय विपक्ष ने चुप्पी साध ली थी लेकिन चुनाव के दौरान किस तरह की गड़बड़ी होती है इसका खुलासा सबसे पहले राहुल गांधी ने किया था चुनाव आयोग ने अभी तक उसे पत्रकार वार्ता का जवाब नहीं दिया पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता सड़क से लेकर अदालत तक यह लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं पश्चिम बंगाल अपने अधिकारों के प्रति काफी जागरूक रहता है जिसके कारण भाजपा को पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है टीएमसी का नेटवर्क गांव गांव तक फैला हुआ है जिस तरह से टीएमसी चुनाव आयोग के हर रिकॉर्ड को न केवल अपने पास संरक्षित कर रही है वरन चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जो मतदाता सूची जारी की जा रही है उसमें जरा सी भी गड़बड़ी होने पर कोर्ट पहुंच जाती है ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और भाजपा को बुरी तरह से घेर लिया है पश्चिम बंगाल पहला राज्य होगा जहां से चुनाव आयोग के कारण भाजपा को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है पश्चिम बंगाल में चर्चाओं के दौरान यह कहा जा रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार भाजपा के लिए आगे चलकर भस्मासुर बन सकते हैं। चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वह भाजपा नेताओं के इशारे पर उनके मनपसंद अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव कार्य में लगा रहे हैं बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी गड़बड़ी होगी उस सबके लिए वह चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर जो न्यायिक अधिकारी मतदाता सूची के काम में लगे हुए हैं उनको बंधक बनाए जाने के बाद किस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति है यह सुप्रीम कोर्ट के सामने उजागर हो गया है। पश्चिम बंगाल में अभी मतदाता सूची फाइनल नहीं हुए हैं जल्द ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित कर पाना आसान नहीं होगा ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से अलग-अलग करके रखा है मानवाने तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो भी गड़बड़ी होगी या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी उसके लिए चुनाव आयोग और भाजपा को जिम्मेदार ठहराना ममता बनर्जी के लिए आसान हो गया है। पहली बार एसआईआर के दौरान जो गड़बड़ियां हुई है वह सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में आ गई है यह सही है कि कानून दान केंद्रीय चुनाव आयोग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है लेकिन जिस तरह से जनता उत्तेजित हो रही है उसका काम में आज कहीं ना कहीं केंद्रीय चुनाव आयोग और भाजपा को भुगतना पड़ सकता है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पर विपक्ष का विरोध

सौरभ वार्ष्णेय

भारत में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ माने जाते हैं। सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाली और आपदा प्रबंधन तक, इन बलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में जब भी इनके ढांचे, सेवा शर्तों या अधिकारों से जुड़ा कोई नया विधेयक या सुधार प्रस्ताव सामने आता है, तो स्वाभाविक रूप से व्यापक चर्चा होती है। लेकिन हाल के समय में देखा गया है कि विपक्ष इन प्रस्तावों का मुखर विरोध कर रहा है। यह विरोध किन कारणों से प्रेरित है, इसे समझना जरूरी है।

सबसे पहली चिंता संघीय ढांचे (फेडरल स्ट्रक्चर) को लेकर है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के माध्यम से राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप बढ़ा सकती है। यदि किसी विधेयक में बलों को अधिक स्वायत्तता या सीधे हस्तक्षेप के अधिकार दिए जाते हैं, तो यह राज्यों की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी को कमजोर कर सकता है। यही कारण है कि कई विपक्षी दल इसे राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण के रूप में देखते हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा बलों के कर्मियों के अधिकारों और कल्याण से जुड़ा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सुधार के नाम पर अनुशासन और नियंत्रण को तो मजबूत कर रही है, लेकिन जवानों की समस्याओं—जैसे लंबी ड्यूटी, मानसिक तनाव, वेतन विसंगतियां और पेंशन—पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। यदि किसी विधेयक में इन मुद्दों का संतुलित समाधान नहीं होता, तो उसका विरोध स्वाभाविक है।

तीसरा पहलू राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका है। विपक्ष को डर है कि सीएपीएफ का इस्तेमाल राजनीतिक विरोध को दबाने या चुनावी लाभ के लिए किया जा सकता है। भारत जैसे लोकतंत्र में सुरक्षा बलों की निष्पक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी ऐसे प्रावधान पर सवाल उठना लाजिमी है जो इस निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता

है।

हालांकि, यह भी सच है कि कई बार विरोध का कारण केवल नीतिगत असहमति नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति भी होती है। संसद में सरकार को घेरने और जनमत को प्रभावित करने के लिए विपक्ष अक्सर ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाता है। इससे बहस तो होती है, लेकिन कई बार सार्थक समाधान पीछे छूट जाते हैं। इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएपीएफ जैसे संवेदनशील विषय पर निर्णय लेते समय संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखी जाए। सरकार को चाहिए कि वह सभी हितधारकों—राज्यों, सुरक्षा विशेषज्ञों और स्वयं बलों के कर्मियों—से व्यापक संवाद करे। वहीं विपक्ष को भी केवल विरोध तक सीमित न रहकर रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। सुरक्षा और लोकतंत्र दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) सुधारों पर सहमति और संवाद का रास्ता ही देशहित में सबसे उपयुक्त साबित होगा।

भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) — जैसे (सीआरपीएफ), (बीएफएफ), (आईटीबीपी), (सीआईएसएफ) और (एसएसबी) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सीमाओं की रक्षा से लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बनाए रखने तक, इन बलों ने लगातार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश की सेवा की है। ऐसे में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक का प्रस्ताव न केवल प्रशासनिक सुधार का विषय है, बल्कि यह देश की सुरक्षा संरचना को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है।

इस विधेयक का मूल उद्देश्य (सीएपीएफ) के कार्य, अधिकार और जवाबदेही को एक समान कानूनी ढांचे में लाना है। वर्तमान में अलग-अलग बलों के लिए अलग-अलग कानून और नियम हैं, जिससे समन्वय और निर्णय प्रक्रिया में जटिलताएं पैदा होती हैं। एक समेकित विधेयक इन समस्याओं को दूर कर सकता है, जिससे संचालन में स्पष्टता और दक्षता आएगी।हालांकि, इस प्रस्ताव के साथ कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं भी जुड़ी हैं। सबसे बड़ी चिंता बलों के अधिकारों और कर्मियों के कल्याण को लेकर है। (सीएपीएफ)के जवान लंबे समय से बेहतर कार्य-परिस्थितियों, निश्चित कार्य-घंटों, और पेंशन संबंधी मुद्दों को उठाते रहे हैं। यदि यह विधेयक केवल प्रशासनिक केंद्रीकरण तक सीमित रह जाता है और जवानों की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज करता है, तो इसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।

इसके अलावा, संघीय ढांचे पर इसके प्रभाव को भी समझना जरूरी है। राज्यों की पुलिस व्यवस्था और ट्रक्स्स के बीच संतुलन बनाए रखना एक संवेदनशील विषय है। यदि केंद्र के अधिकार अत्यधिक बढ़ते हैं, तो यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप का कारण बन सकता है, जिससे संघीय संतुलन प्रभावित हो सकता है।

इस विधेयक के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, जवानों के मानसिक स्वास्थ्य, परिवार से दूरी, और कठिन परिस्थितियों में काम करने जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ठोस प्रावधान किए जाएं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक एक अवसर है—सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ उन जवानों के जीवन को बेहतर बनाने का, जो दिन-रात देश की रक्षा में लगे हैं। यह तभी सार्थक होगा, जब सुरक्षा के साथ संवेदनशीलता और शक्ति के साथ संतुलन भी सुनिश्चित किया जाए।

ईरान का भीषण प्रहार और इजरायल की अग्निपरीक्षा

दिलीप कुमार पाठक

आज मध्य-पूर्व के तपते और बारूद की गंध से भरे रेगिस्तान में इतिहास की सबसे खतरनाक पटकथा लिखी जा रही है और दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ अमेरिका जैसी महाशक्ति की हेकड़ी ईरान के फौलादी इरादों के सामने पस्त पड़ती दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो व्हाइट हाउस की कुर्सी संभालते ही ईरान को पत्थर युग में भेजने की गर्जना कर रहे थे, आज उसी ईरान की अभूतपूर्व सैन्य दृढ़ता और अचूक मिसाइल तकनीक के सामने खुद को बुरी तरह फंसा हुआ पा रहे हैं। ट्रंप का हालिया और चौंकाने वाला बयान, जिसमें उन्होंने अगले 2 से 3 हफ्तों के भीतर ईरान से अपनी सेना को बाहर निकालने की बात कही है, दरअसल कोई सोची-समझी कूटनीतिक जीत नहीं बल्कि एक हारी हुई बाजी से सुरक्षित निकलने की छटपटाहट है क्योंकि अमेरिका की वैश्विक दादागिरी अब ईरान के आत्मसम्मान और उसकी मज़बूत सैन्य घेराबंदी के सामने धराशायी हो चुकी है। ट्रंप जो खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डील मेकर कहते थे, आज ईरान की शर्तों के सामने बेबस और लाचार नज़र आ रहे हैं और उनकी शांति की बात दरअसल उनकी अपनी सैन्य विफलता और रणनीतिक हार को छिपाने का एक पारदर्शी पर्दा मात्र है। वे भली-भांति जानते हैं कि अगर वे अब इस युद्ध के मैदान से बाहर नहीं निकले, तो अमेरिका को एक ऐसे क्षेत्रीय महायुद्ध का सामना करना पड़ेगा जिसकी तबाही की आंच सीधे वाशिंगटन की दहलीज तक पहुँचेगी, क्योंकि ईरान ने साफ़ कर दिया है कि मध्य-पूर्व अब अमेरिका की जागीर नहीं है। ईरान का पक्ष आज इस संघर्ष में एक अजेय विजेता की तरह उभरा है जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि वह अब केवल रक्षात्मक मुद्रा में नहीं रहेगा बल्कि आक्रामक रक्षा की नीति अपनाते हुए दुश्मन को उसके घर में घुसकर तबाह करेगा। हाल ही में तेल अवीव की अभेद्य कही जाने वाली सुरक्षा दीवारों को भेदती ईरानी मिसाइलों और जॉर्डन स्थित अमेरिकी अड्डों पर हुए अचूक हमलों ने यह साबित कर दिया है कि ईरान की सैन्य शक्ति को कम आंकना ट्रंप की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। ईरान ने न केवल अमेरिकी धमकियों को कूड़ेदान में डाल दिया है बल्कि अपनी सैन्य श्रेष्ठता के दम पर युद्ध का भूगोल बदलने की ऐसी चुनौती दी है जिससे ट्रंप अंतरराष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह अलग-थलग और लाचार पड़ गए हैं। इस बीच, ट्रंप के पीछे हटने के फैसले ने मध्य-पूर्व की बिसात पर एक ऐसा पावर वैक्यूम पैदा कर दिया है जिसे भरने के लिए रूस और चीन भूखे भेड़ियों की तरह घात लगाकर बैठे हैं और जैसे ही अमेरिकी सेना के कदम पीछे हटेंगे, पुतिन अपनी सैन्य साख और शी जिनपिंग अपनी असीमित आर्थिक शक्ति के ज़रिए इस तेल-समृद्ध क्षेत्र को पूरी तरह अपने प्रभाव में ले लेंगे। ट्रंप की यह एग्जिट चीन के लिए वह सुनहरा रास्ता खोल रही है जहाँ वह बिना एक भी गोली चलाए मध्य-पूर्व का नया आर्थिक और रणनीतिक महाबली बनकर उभरेगा, जो सीधे तौर पर अमेरिकी वैश्विक वर्चस्व के अंत का औपचारिक एलान होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा बेचैनी, गुस्सा और असुरक्षा इज़रायल के खेमे में दिखाई दे रही है, जिसके लिए ट्रंप का यह एग्जिट प्लान किसी बड़े कूटनीतिक विश्वासघात और सीधे तौर पर मौत के वारंट से कम नहीं है क्योंकि इज़रायल का स्पष्ट मानना है कि अमेरिका का पीछे हटना ईरान को पूरे क्षेत्र का बेताज और अनियंत्रित बादशाह बना देगा। इज़रायल आज खुद को इस युद्ध में ठगा हुआ और अकेला महसूस कर रहा है और उसने अपने सैन्य बजट में 10 बिलियन की जो ऐतिहासिक और भारी वृद्धि की है, वह दुनिया को यह जताने के लिए काफी है कि वह अब अकेले ही इस महायुद्ध में उतरने को तैयार है।

क्या सच में भगवान शिव की कोई पुत्री थी?

भगवान शिव जी को हम सभी देवों के देव महादेव के रूप में जानते हैं, जिनकी पूजा पूरे भारत में बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है। उनकी छवि एक ऐसे देवता की है जो बेहद सरल, भोले और जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। आम तौर पर जब भी शिव परिवार की बात होती है तो सबसे पहले माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय का नाम सामने आता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ पौराणिक मान्यताओं में शिव जी की एक पुत्री का भी जिक्र मिलता है। यही कारण है कि लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या सच में शिव जी की कोई बेटी थी, अगर थी तो उसका नाम क्या था और उसकी कहानी क्या है।

इस विषय को लेकर अलग-अलग पुराणों और कथाओं में अलग अलग बातें कही गई हैं, जिससे कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। आज हम इसी सवाल का सरल और साफ जवाब देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पूरी जानकारी एक ही जगह मिल सके।

शिव जी की पुत्री का नाम क्या था

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी की पुत्री का नाम अशोकसुंदरी बताया जाता है। यह नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि उनकी पूजा और कथा उतनी प्रचलित नहीं है जितनी गणेश जी या कार्तिकेय की है। कहा जाता है कि अशोकसुंदरी का जन्म माता पार्वती की इच्छा से हुआ था। इस वजह से उन्हें शिव और पार्वती की बेटी माना जाता है।

अशोकसुंदरी की उत्पत्ति की कहानी

अशोकसुंदरी की कहानी बहुत दिलचस्प है। एक कथा के अनुसार, माता पार्वती एक बार अकेलापन महसूस कर रही थीं। तब उन्होंने कल्पवृक्ष से एक पुत्री की कामना की। कल्पवृक्ष को इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष माना जाता है। जैसे ही माता पार्वती ने इच्छा की, वहां से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिसे अशोकसुंदरी नाम दिया गया। इस नाम का मतलब भी खास है। "अशोक" यानी दुख दूर करने वाली और "सुंदरी" यानी सुंदर। यानी ऐसी सुंदर कन्या जो दुखों को दूर कर दे। इस तरह अशोकसुंदरी को सुख और खुशी का प्रतीक माना जाता है।

अशोकसुंदरी का विवाह और जीवन

कथाओं के अनुसार अशोकसुंदरी का विवाह राजा नहुष से होना तय था। नहुष एक शक्तिशाली और तेजस्वी राजा थे। लेकिन उनके जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए। एक राक्षस ने अशोकसुंदरी को पाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने धर्म और वचन का पालन किया। अंत में अशोकसुंदरी का विवाह नहुष से ही हुआ और उन्होंने एक आदर्श जीवन जिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर इंसान अपने रास्ते पर अडिग रहता है तो अंत में जीत उसी की होती है।

क्या शिव जी की और भी बेटियां थीं

अब सवाल आता है कि क्या शिव जी की सिर्फ एक ही बेटी थी या और भी बेटियां थीं। अधिकतर पौराणिक ग्रंथों में सिर्फ अशोकसुंदरी का ही जिक्र मिलता है। हालांकि कुछ लोक कथाओं और क्षेत्रीय मान्यताओं में अलग अलग नामों का उल्लेख किया गया है, लेकिन उनका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए अगर प्रमाणिक और प्रसिद्ध मान्यता की बात करें तो शिव जी की पुत्री के रूप में अशोकसुंदरी का ही नाम सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाता है।

क्यों कम सुनी जाती है अशोकसुंदरी की कथा

आप सोच रहे होंगे कि अगर शिव जी की बेटी थी तो फिर उनके बारे में ज्यादा क्यों नहीं बताया जाता। इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म में कुछ देवी देवताओं की पूजा और कथाएं ज्यादा लोकप्रिय हो गई हैं, जैसे गणेश जी और कार्तिकेय। अशोकसुंदरी की कथा मुख्य रूप से पद्म पुराण में मिलती है, लेकिन आम लोगों तक यह उतनी नहीं पहुंच पाई। यही वजह है कि उनके बारे में जानकारी कम मिलती है।

इस कथा से क्या सीख मिलती है

अशोकसुंदरी की कहानी हमें कई बातें सिखाती है। सबसे पहली बात यह कि जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह कि सच्चाई और विश्वास हमेशा जीतते हैं। तीसरी बात यह कि हर रिश्ते का अपना महत्व होता है, चाहे वह कम प्रसिद्ध ही क्यों न हो। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हर पौराणिक कथा के पीछे एक गहरा संदेश छुपा होता है, जिसे समझना जरूरी है।

खिलौने के व्यापारी की राजा को सीख

अगर हम सही तरीके से सुनना, समझना और बोलना सीख जाएं, तो जीवन सफल और संतुलित हो जाएगा

पुराने समय में एक राजा को नए-नए खिलौने खरीदने का बहुत शौक था। उसके दरबार में समय-समय पर दूर-दूर से व्यापारी आते और अनोखी वस्तुएं प्रस्तुत करते। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और आत्मविश्वास से बोला, "राजन्, आज मैं आपको ऐसे खिलौने दिखाने वाला हूं, जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे।"

राजा उत्सुक हो उठा। उसने तुरंत व्यापारी को अपने खिलौने दिखाने का आदेश दिया। व्यापारी ने अपने झोले से तीन सुंदर पुतले निकाले। देखने में तीनों बिल्कुल एक जैसे थे, पर उनकी कीमतें अलग-अलग थीं। पहले की कीमत एक लाख मोहरें, दूसरे की एक हजार मोहरें और तीसरे की केवल एक मोहर।

राजा और दरबारियों को यह बात बहुत अजीब लगी। सभी ने पुतलों को ध्यान से देखा, पर उनमें कोई अंतर समझ नहीं आया। तब राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री से इस रहस्य को समझाने के लिए कहा।

मंत्री ने ध्यानपूर्वक पुतलों का निरीक्षण किया और एक सेवक से कुछ तिनके मंगवाए। उसने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। तिनका उसके पेट में चला गया और थोड़ी देर बाद उसके होंठ हिले और फिर बंद हो गए। दूसरे पुतले के कान में तिनका डाला तो वह सीधे दूसरे कान से बाहर निकल गया। तीसरे पुतले के कान में तिनका डालते ही उसका मुंह खुल गया और वह जोर-जोर से हिलने लगा।

मंत्री ने मुस्कुराते हुए समझाया, "राजन, ये पुतले हमें जीवन की गहरी सीख देते हैं। पहला पुतला उन लोगों का प्रतीक है जो बातों को ध्यान से सुनते हैं, उन्हें समझते हैं, सत्यता परखते हैं और फिर ही कुछ कहते हैं। इसलिए इसकी कीमत सबसे अधिक है।"

"दूसरा पुतला उन लोगों को दर्शाता है जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। उन्हें किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, वे लापरवाह होते हैं।" "तीसरा पुतला उन लोगों जैसा है जो बिना सोचे-समझे हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं और बिना सत्य जाने उसे फैलाते हैं। ऐसे लोगों का मूल्य बहुत कम होता है।" राजा और दरबारियों को यह सीख समझ में आ गई कि अगर हम सही तरीके से सुनना, समझना और बोलना सीख जाएं, तो जीवन सफल और संतुलित हो जाएगा। राजा ने उस व्यापारी से तीनों पुतले खरीद लिए।

प्रसंग की सीख

सुनने की कला विकसित करें

पहले पुतले की तरह बनें। जब कोई कुछ कहे, तो उसे ध्यान से सुनें। अधूरी जानकारी पर प्रतिक्रिया देने से गलतफहमियां पैदा होती हैं। एक अच्छा श्रोता ही सही निर्णय ले सकता है।

प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें

आज के समय में लोग तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि पहले सोचें, फिर बोलें।

बातों को इधर-उधर करने से बचें

तीसरे पुतले की तरह बिना जांचे-परखे बातें इधर-उधर फैलाना आपके व्यक्तित्व को कमजोर करता है। इससे विश्वास कम होता है और रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। इसलिए सोच-विचार कर किसी बात को आगे बढ़ाएं।

आत्म-नियंत्रण रखें

अपनी भावनाओं और शब्दों पर नियंत्रण रखना जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वही सफल होता है।

सही लोगों की पहचान करें

जीवन में ऐसे लोगों के साथ रहें जो समझदारी से बात करते हैं और सोच-समझकर निर्णय लेते हैं। गलत संगति आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है।

ज्ञान और विवेक को प्राथमिकता दें

कीमत हमेशा बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर की समझ और विवेक से तय होती है। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान दें।

संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं

हर स्थिति को अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। इससे निर्णय बेहतर होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है।

विपरीत वातावरण में सिर्फ अध्यात्म से मिलेगी शांति

झूठ बोलना एक विकल्प है, जिसे हम चुनते हैं। क्योंकि जिसे झूठ बोलना आता है, वो सच तो बोल ही सकता है। लेकिन जब भी हमारे पास चयन का अवसर आता है, हम सच को कठिन और झूठ को आसान मान लेते हैं। पहले कहा जाता था कि गांव के लोग सच्चे हैं और शहर में गली-गली, डगर-डगर झूठ बसता है।

लेकिन अब बेईमानी, निकम्मापन, झूठ- सब जगह पसर गया, क्या शहर, क्या गांव? वर्तमान युद्ध ने शहरी जीवन को हिला के रख दिया है। बचत में गिरावट आ गई, जिसके परिणाम भविष्य में दिखेंगे। ये तो तय है कि मनुष्य के शहरी जीवन में पिछले 20 सालों में हमने जो परिवर्तन और प्रगति की है, वो पिछले 2 हजार साल में नहीं हुई।

डिजिटल मीडिया ने एक नियम पकड़ लिया कि लोगों को इतना प्रभावित कर दिया जाए कि वो उसकी बात मानें। प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और अपराध शहर के विकास का हिस्सा बन गए। ऐसे में सिर्फ आध्यात्मिक गलियारे हैं, जहां मनुष्य को ऐसे विपरीत वातावरण में रहते हुए भी शांति मिल सकती है।

अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं वीर हनुमान

हनुमान जी को प्राप्त 8 सिद्धियां

सिद्धियां आठ प्रकार की दिव्य संपत्तियां हैं, जिन्हें पा लेने के बाद किसी अन्य धन-संपत्ति की जरुरत नहीं रहती।

अणिमा यानि बहुत सूक्ष्म रूप धारण करने की शक्ति।

महिमा, इच्छानुसार बहुत बड़ा रूप धारण करने की शक्ति।

गरिमा यानि शरीर को अत्यंत भारी बनाने की शक्ति।

लघिमा यानि शरीर को अत्यंत हल्का बनाने की शक्ति।

प्राप्ति या किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेने की शक्ति।

प्राकाम्य यानि इच्छानुसार किसी भी जगह पहुंचने, पानी में रहने या आकाश में उड़ने की शक्ति।

ईशित्व यानि दैवीय शक्तियों का नियंत्रण करना।

वशित्व यानि इंद्रियों और मन पर पूर्ण नियंत्रण।

हनुमान जी को प्राप्त 9 निधियां

9 निधियां नौ प्रकार की दिव्य संपत्तियां हैं, जिन्हें पा लेने के बाद किसी अन्य धन-संपत्ति की जरुरत नहीं रहती।

पद्म निधि या स्वर्ण-चांदी का संग्रह कर दान करने वाला सात्विक स्वभाव।

महापद्म निधि धार्मिक कार्यों में धन लगाने वाला स्वभाव।

नील निधि यानि तीन पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति।

मुकुंद निधि यानि राज्य और सत्ता से संबंधित संपत्ति।

नंद निधि यानि कुल का आधार बनने वाली संपत्ति।

मकर निधि यानि अस्त्र-शस्त्रों का संग्रह।

कच्छप निधि में स्वयं उपभोग करने वाली संपत्ति।

शंख निधि में एक पीढ़ी तक रहने वाली संपत्ति।

खर्व निधि यानि मिश्रित फलों वाली संपत्ति।

इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों की वजह से हनुमान जी अद्भुत और चमत्कारी हैं। उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है।

इन सिद्धियों की वजह से श्रीरामदूत किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, पल भर में कहीं भी पहुंच सकते हैं और असंभव कार्यों को भी संभव बना देते हैं।

हनुमान चालीसा के पाठ से भक्तों को इन दिव्य शक्तियों और संपत्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संकटमोचन की कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, साहस बढ़ता है और जीवन में सफलता मिलती है।

अनोखा मंदिर, जहां कैद में हैं संकटमोचन क्यों हनुमान जी के पैरों में डाली गई बेड़ियां?

जगन्नाथ मंदिर के पास ही रामदूत हनुमान जी का भी एक मंदिर है, जिसे बेड़ी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी के पैरों में बेड़ियां डाली गई हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है?

जगन्नाथ भगवान के धाम (मंदिर) को चारों धामों में से एक माना जाता है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। भगवान जगन्नाथ कोई और नहीं, बल्कि श्री हरि विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण हैं। भगवान इस मंदिर में अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा, जिसे इस मंदिर के बारे में पता न हो। ये मंदिर देश के साथ-साथ विदेशों में भी प्रसिद्ध है।

लोग देश-विदेश से इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यहां मंदिर की रक्षा कौन करता है। आप जानकर हैरान होंगे कि इस मंदिर की रक्षा स्वयं भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास ही रामदूत हनुमान जी का भी एक मंदिर है, जिसे बेड़ी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी के पैरों में बेड़ियां डाली गई हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है?

बेड़ी हनुमान मंदिर को लेकर ये है मान्यता

लोक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने कराया था। कहा जाता है कि उनको स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन देकर इस मदिर का निर्माण कराने का आदेश दिया था। कहते हैं कि यहां कण-कण में बजरंगबली का वास है। वहीं बेड़ी हनुमान मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि समय समुद्र की तेज लहरों ने तीन बार जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया।

आज भी हनुमान जी कर रहे हैं आदेश का पालन

उस समय भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वो मंदिर में पहरा दें और समुद्र की लहरों को नियंत्रित करें। भगवान जगन्नाथ के आदेश पर हनुमान जी ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे निभाई, लेकिन जब भी हनुमान जी कहीं पर भी श्रीराम का भजन या किर्तन सुनते है वो पहरेदारी छोड़कर उस जगह पर चले जाते। ऐसे में समुद्र की लहरें अवसर पाकर मंदिर में प्रवेश कर लेतीं।

यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को वहां सोने की बेड़ियों से बांध दिया। ताकि हनुमान हमेशा-हमेशा उस जगह पर रहें और मंदिर की रक्षा करते रहें। आज भी हनुमान जी भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं।

वैशाख माह में करें इन चीजों का दान

जल: वैशाख मास में जल का दान सबसे पुण्यकारी माना गया है। इस माह में जल का अर्घ्य अर्पित करने से सूर्य देव बहुत प्रसन्न होते हैं। वैशाख में जल से भरा घड़ा यानी मटके का दान करें।

फल: वैशाख महीने में ऐसे फलों का दान अवश्य करें, जिनको खाने से शितलता मिलती हो। इस माह में मौसमी फल जैसे- तरबूज, **खरबूजा और बेल का दान** बहुत शुभ माना गया है। फल का दान करने से घर में सुख-समृद्धि रहती है।

छाता और चप्पल: वैशाख महीने में गर्मी बहुत रहती है। ऐसे में गरीब और जरूरतमंदों को छाता और चप्पल दान में दें। इन दोनों चीजों का दान कुंडली से राहु-केतु जैसे दोष दूर करता है।

वस्त्र: वैशाख मास में जरूरतमंदों को वस्त्र का दान करें। इस माह में वस्त्रों के दान से कुंडली में सूर्य कि स्थिति मजबूत होती है।

सत्तू: गर्मियों में सत्तू का सेवन पेट को ठंडा रखता है। इसलिए इस माह में सत्तू का सेवन जरूर करें। साथ ही सत्तू का दान भी अवश्य करें।

अप्रैल 2026 में 15 अप्रैल से गूंजेंगी शहनाइयां

अप्रैल 2026 के विवाह के शुभ मुहूर्त

15 अप्रैल 2026 (बुधवार)
20 अप्रैल 2026 (सोमवार)
21 अप्रैल 2026 (मंगलवार)
25 अप्रैल 2026 (शनिवार)
26 अप्रैल 2026 (रविवार)
27 अप्रैल 2026 (सोमवार)
28 अप्रैल 2026 (मंगलवार)
29 अप्रैल 2026 (बुधवार)

15 अप्रैल से क्यों शुरू होते हैं शुभ कार्य?

हिंदू पंचांग के अनुसार, खरमास के दौरान सूर्य देव गुरु की राशि (धनु या मीन) में होते हैं, जिस कारण विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। अप्रैल 2026 में खरमास की समाप्ति 14 अप्रैल को हो रही है, इसलिए 15 अप्रैल से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन के बाद ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति अनुकूल हो जाती है, जिससे विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए शुभ संयोग बनते हैं।

अक्षय तृतीया का विशेष महत्व

अप्रैल के महीने में ही 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया का पावन पर्व भी पड़ रहा है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना गया है। यानी इस दिन बिना पंचांग देखे भी विवाह संपन्न किए जा सकते हैं। यही कारण है कि अप्रैल के माह में शादियों की सबसे ज्यादा धूम रहती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

एफसीआरए बिल पर रिजिजू की कांग्रेस को चेतावनी

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के बारे में फैलाई जा रही झूठ को सरकार बेनकाब करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में ईसाई मिशनरियों से बातचीत की गई है ताकि उनकी चिंताओं का समाधान संवाद के माध्यम से किया जा सके। मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि हमने केरल में ईसाई मिशनरियों से बातचीत की है और उनकी चिंताओं को सुना है। हमें सवाल-जवाब और संवाद के माध्यम से मिलकर काम करने की जरूरत है। मंत्री ने दावा किया कि हमने सभी चिंताओं को सुना है और केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का इरादा किसी भी धर्म या जाति के खिलाफ काम करने का नहीं है। अगर कम्युनिस्ट और कांग्रेस झूठ फैलाना जारी रखते हैं, तो हम उन्हें बेनकाब करेंगे।

असम सीएम हिमंता का ओवैसी पर तीखा हमला

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 4 अप्रैल को असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि एआईयूडीएफ के समर्थन में असम दौरे के दौरान उनके चुनावी भाषणों का मकसद राजनीतिक लाभ के लिए मिया समुदाय का इस्तेमाल करना है। उन्होंने कांग्रेस पर ऐसे बयानों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। सरमा ने दावा किया कि कांग्रेस ने चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने और मतदाताओं को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत करने के लिए ओवैसी को असम में भेजा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ओवैसी के भाषणों से आबादी के कुछ खास वर्गों को लामबंद करने की कोशिशें झलकती हैं। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ऐसे बयानों की आलोचना करने में विफल रही है और यूनुस तमूली और यूनुस अली जैसे लोगों से जुड़े विवादास्पद बयानों और घटनाओं पर चुप रही है। अपने चुनावी विश्वास को दोहराते हुए सरमा ने कहा कि भाजपा 90-100 सीटें जीतने की स्थिति में है।

सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे को किया फोन

मुंबई। बारामती उपचुनाव से पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने हाल ही में उद्धव ठाकरे से आगामी चुनाव के संबंध में बात की। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब कई पार्टियां इस बात पर चर्चा कर रही हैं कि क्या चुनाव निर्विरोध कराया जाना चाहिए। खबरों के मुताबिक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार गुट) और सत्ताधारी गठबंधन के नेता बारामती में निर्विरोध चुनाव के पक्ष में हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) ने भी इसी तरह का रुख अपनाते हुए कहा है कि वह पवार परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बारामती को लंबे समय से पवार परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। हालाँकि, स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अगर सहयोगी दल चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है।

तमिलनाडु चुनाव में के. अन्नामलाई क्यों नहीं लड़ रहे?

चेन्नई। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की उम्मीदवारी सूची में अपना नाम न होने पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि चुनाव न लड़ने का फैसला पूरी तरह से उनका अपना था। कोयंबटूर से चेन्नई पहुंचने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि उन्होंने अपने इस फैसले की जानकारी पार्टी नेतृत्व को लिखित रूप में काफी पहले ही दे दी थी। उन्होंने कहा कि मैंने कोर कमेटी को पहले ही बता दिया है कि मैं किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए, ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट देने से इनकार किया गया। सच तो यह है कि मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। अपनी उम्मीदवारी को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए अन्नामलाई ने सवाल उठाया कि जब उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, तो नेतृत्व उन्हें सीट कैसे दे सकता है। उन्होंने कहा कि जब मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता, तो नेतृत्व मुझे टिकट कैसे दे सकता है?

केरल में बुजुर्ग बनेंगे किंगमेकर पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा

तिरुवनंतपुरम। केरल में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल बज चुका है। इस बार राज्य की राजनीति में युवा चेहरों से ज्यादा चांदी जैसे बालों वाले मतदाताओं, यानी वरिष्ठ नागरिकों का दबदबा दिखाई दे रहा है। केरल की 16.5% आबादी अब बुजुर्गों की श्रेणी में है, जो देश में सबसे अधिक है। यही कारण है कि पेंशन, स्वास्थ्य और सुरक्षा इस चुनाव के सबसे निर्णायक मुद्दे बनकर उभरे हैं। राज्य की वृद्ध आबादी 16.5 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जो देश में सबसे अधिक है, और वरिष्ठ नागरिक एक प्रभावशाली मतदाता वर्ग बन गए हैं। विथुरा निवासी 81 वर्षीय कृष्णाम्मा के लिए चुनाव का सार एक सीधे सवाल में सिमट गया है। पहाड़ी इलाके में स्थित उनके साधारण, टाइल की छत वाले घर पर जब पार्टी कार्यकर्ता वोट मांगने पहुंचे तो उन्होंने सीधा सवाल किया, मुझे मेरी अगली पेंशन कब मिलेगी?

अल्पसंख्यकों पर हमला करने वाले लोगों के साथ सीएम विजयन?

100 सीट जीतकर बनाएंगे सरकार : राहुल

अलप्पुझ। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक गठबंधन (एलडीएफ) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि देश के अन्य हिस्सों में अल्पसंख्यकों पर हमला करने वाले लोगों के साथ मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सांठगांठ है। गांधी ने यहां एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा-एलडीएफ के बीच गठजोड़ का आरोप दोहराया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर चुनाव प्रचार के दौरान शबरिमला मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। राज्य की 140 विधानसभा सीट पर नौ अप्रैल को मतदान होना है।

कांग्रेस नेता के साथ मंच साझा करने वाले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पूर्व नेता जी सुधाकरन का जिक्र करते हुए गांधी ने कहा कि उनकी मौजूदगी एलडीएफ के भीतर गहरी दरार का संकेत है। सुधाकरन अंबलपुझा से यूडीएफ के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। गांधी ने कहा, मंच पर एक वरिष्ठ वामपंथी नेता बैठे हैं। इसके पीछे कारण है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अचानक अपनी सोच बदल ली है। जो लोग वर्षों तक किसी राजनीतिक संगठन में रहते हैं, वे उसके मूल्यों को आत्मसात कर लेते हैं। वे अवसरवादी रुख के कारण यहां नहीं हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि एलडीएफ में मूल भावना बदल गई है।

उन्होंने कहा, एलडीएफ का मतलब है 'वाम लोकतांत्रिक मोर्चा', लेकिन अब साफ तौर पर उसमें कुछ भी 'वामपंथी' नहीं रह गया है। चुनाव के बाद स्थिति और भी बदतर हो जाएगी।'' गांधी ने आरोप लगाया कि एलडीएफ ऊपर से कुछ और दिखती है, लेकिन असल में उसकी दिशा कहीं और से तय हो रही है, इसी कारण उसके नेता व कार्यकर्ता भी असहज हैं।

उन्होंने कहा, एलडीएफ पर ऐसी ताकतों का प्रभाव है जो सांप्रदायिक राजनीति करती हैं, भारत के संविधान को नहीं मानतीं, लोगों को बांटती हैं और नफरत फैलाती हैं। केरल में हर कोई भाजपा, आरएसएस तथा माकपा के बीच संबंध देख सकता है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एलडीएफ में दो तरह के नेता हैं-एक वे जो सत्ता के लिए अवसरवादी रुख अपनाते हैं। भाजपा-आरएसएस के समर्थन की परवाह नहीं करते, तथा दूसरे वे जो वर्षों तक पार्टी के लिए काम करने के बाद अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह अन्य राज्यों में अपने भाषणों में धर्म और मंदिरों की बात करते हैं, लेकिन केरल में शबरिमला से जुड़े मुद्दों पर चुप रहते हैं।

उन्होंने कहा, मैं भाजपा और आरएसएस का सामना करता हूं। वे मुझ पर हमला करते हैं, मेरे खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं, मुझसे पूछताछ होती है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटता। मोदी मुझ पर रोज हमला करते हैं, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री व उनके परिवार पर कुछ क्यों नहीं बोलते? जब मोदी केरल आते हैं, तो वह धर्म और मंदिरों की बात नहीं करते, क्योंकि वह एलडीएफ की मदद करना चाहते हैं।

सच्चाई यह है कि वह जानते हैं कि एलडीएफ उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती नहीं देगा। उन्होंने दावा किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। गांधी ने कहा, यहां की दो नन पर छत्तीसगढ़ में हमला हुआ, मणिपुर में चर्च जलाए गए। जो लोग अल्पसंख्यकों-मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों पर हमला कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मुख्यमंत्री की सांठगांठ है।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, दोनों ही लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद अहंकारी हो गए हैं और उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जब संसद में पांच-छह महिला सांसद खड़ी हुईं, तो मोदी ने इसे अपने ऊपर हमले के तौर पर देखा। विजयन के बारे में भी ऐसी ही तुलना करते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि जब कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए तो उन्हें पीट-पीटकर अधमरा कर दिया गया।'' उन्होंने कहा, उन्हें लगता है कि लोग उन पर हमला कर देंगे, इसलिए वे पहले ही हमला कर देते हैं। ये दोनों सत्ता के नशे में चूर नेताओं के उदाहरण हैं, जिन्होंने जनता से अपना नाता तोड़ लिया है।

राहुल गांधी का राजनीतिक एजेंडा ध्वस्त!

कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने खुलकर की पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भले ही मोदी सरकार की विदेश नीति को विफल साबित करने के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हों, लेकिन उनकी ही पार्टी के अनुभवी और कूटनीति समझने वाले दिग्गज नेता अब खुलकर इस नैरेटिव को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। वह न केवल मोदी सरकार की रणनीति और संतुलित कूटनीति की सराहना कर रहे हैं, बल्कि यह भी संकेत दे रहे हैं कि जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। यह महज साधारण मतभेद नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर गहराती वैचारिक दरार का खुला प्रमाण है, जहां एक तरफ राहुल गांधी राजनीतिक एजेंडा साधने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता और वैश्विक कूटनीति का अनुभव रखने वाले नेता राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते हुए सच के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं।

हम आपको बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री आनंद शर्मा ने जिस स्पष्टता और दृढ़ता से मोदी सरकार की कूटनीति को परिपक्व और कुशल बताया है, उसने पूरी बहस को नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत ने इस संकट में जिस संतुलन का परिचय दिया है, वही असली कूटनीति है। उन्होंने कहा है कि झुकना या किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव दिखाना भारत जैसे देश के लिए खतरनाक हो सकता था। यह बयान सीधे तौर पर उन नेताओं के मुंह पर तमाचा है जो भारत की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं या उसे एक या दो देशों के पक्ष में झुका हुआ बता रहे हैं।

आनंद शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि मानवीय भी है। खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में संतुलित नीति ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने भारतीय राजनयिकों की भी जमकर तारीफ की और कहा कि वह तिरंगे को ऊंचा रखकर देशवासियों की रक्षा कर रहे हैं। यह बयान उस सोच को मजबूत करता है कि जमीन पर काम करने वाले लोग ही असली नायक होते हैं, न कि केवल बयानबाजी करने वाले नेता।

दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी सरकार की विदेश नीति को सराहा हो। इससे पहले शशि थरूर और मनीष तिवारी भी इसी लाइन पर बोल चुके हैं। मनीष तिवारी ने तो साफ कहा कि यह भारत का युद्ध नहीं है और सरकार ने रणनीतिक स्वायत्तता का सही परिचय दिया है। उन्होंने यह भी माना कि ऊर्जा सुरक्षा, उर्वरक आपूर्ति और क्षेत्र में बसे करोड़ों भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता अब भी सरकार पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पवन खेड़ा ने जहां भारत की वैश्विक भूमिका पर सवाल उठाए, वहीं जयराम रमेश ने इसे कूटनीतिक विफलता तक बता दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब उनकी ही पार्टी के अनुभवी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार नेता सरकार की नीति को सही बता रहे हैं, तो क्या यह आलोचना केवल राजनीतिक मजबूरी बनकर रह गई है?

हम आपको बता दें कि आनंद शर्मा ने एक और महत्वपूर्ण बात कही जो इस पूरे विवाद का सार है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्रीय एकता का परिचय देना चाहिए। इस मुद्दे को राजनीतिक बहस में बदलना देश के साथ अन्याय होगा। उनका यह बयान सीधे तौर पर उन नेताओं को आईना दिखाता है जो हर मुद्दे को राजनीतिक लाभ के नजरिए से देखते हैं।

देखा जाये तो पश्चिम एशिया का यह संकट केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कच्चे तेल, गैस और अन्य संसाधनों पर निर्भर देशों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन चुका है। आनंद शर्मा ने इसे इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकटों में से एक बताया है। ऐसे समय में भारत का संतुलित रुख न केवल जरूरी है बल्कि अनिवार्य भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अब तक अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। जहाजों का सुरक्षित संचालन और जरूरत पड़ने पर उन्हें मोड़ना यह दिखाता है कि सरकार केवल बयान नहीं दे रही बल्कि जमीन पर काम भी कर रही है। यह वही पहलू है जिसे अक्सर विपक्ष नजरअंदाज कर देता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पूरा घटनाक्रम कांग्रेस के भीतर की असहज सच्चाई को उजागर कर रहा है। एक तरफ राहुल गांधी की आक्रामक आलोचना है, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के अनुभवी नेताओं की संतुलित और व्यावहारिक सोच है। यह टकराव आने वाले समय में और गहरा सकता है।

बहरहाल, मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन जब अपने ही दल के वरिष्ठ नेता उसकी तारीफ करें, तो यह साफ संकेत होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस अंदरूनी विरोधाभास को कैसे संभालती है या फिर यह दरार और चौड़ी होती जाती है।

खेल
प्रमुख समाचार

सीएसके की गेंदबाजी पर गावस्कर की चिंता

नई दिल्ली। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने चेन्नई सुपर किंग्स की मौजूदा हालत पर चिंता जताते हुए कहा है कि टीम की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गेंदबाजी बनती जा रही है। आईपीएल 2026 में शुरुआती दोनों मुकाबले हारने के बाद सीएसके दबाव में है, जिसमें पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली हार भी शामिल है।

गावस्कर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए साफ है कि सीएसके को अपनी गेंदबाजी पर तुरंत काम करना होगा। उनके मुताबिक, मौजूदा टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजी इतनी मजबूत हो चुकी है कि सिर्फ 200 या 210 रन बनाना काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएसके को मैच जीतने के लिए लगातार 225 से 230 रन के बड़े स्कोर बनाने पड़ सकते हैं, तभी गेंदबाजों को थोड़ा सहारा मिलेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज की टीमों में बल्लेबाजी की गहराई काफी बढ़ गई है। पंजाब किंग्स जैसी टीम में सातवें नंबर पर मार्कस स्टोइनिस जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं, जिससे लक्ष्य का बचाव करना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सीएसके को अपनी गेंदबाजी इकाई को मजबूत करना ही होगा। इस बीच, युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे की गावस्कर ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि म्हात्रे के लिए बल्लेबाजी क्रम में तीसरा स्थान सबसे उपयुक्त नजर आता है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले मैच में पहली ही गेंद पर आउट होने के बावजूद युवा खिलाड़ी ने आत्मविश्वास नहीं खोया और शानदार वापसी की। गावस्कर के अनुसार, नई पीढ़ी के खिलाड़ियों की यही खासियत है कि वे अतीत को पीछे छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गावस्कर ने रोहित शर्मा की फिटनेस में आए बदलाव की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि रोहित ने अपनी शारीरिक स्थिति पर कड़ी मेहनत की है, जिसका असर उनके खेल में साफ दिखाई दे रहा है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

नए हफ्ते आईपीओ बाजार रहेगा सुस्त, सिर्फ 2 नए इश्यू खुलेंगे

नईदिल्ली। 6 अप्रैल से शुरू हो रहे सप्ताह में प्राइमरी मार्केट में ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिलेगी। इस दौरान केवल दो नए आईपीओ निवेश के लिए खुलेंगे, जिनमें एक मेनबोर्ड और एक एसएमई सेगमेंट से जुड़ा है। वहीं, एक पहले से खुला आईपीओ भी निवेशकों के लिए उपलब्ध रहेगा। सेफ्टी कंट्रोल्स एंड डिवाइसेस का 48 करोड़ रुपए का आईपीओ 6 अप्रैल को खुलेगा और 8 अप्रैल को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड रू. 75-रू. 80 प्रति शेयर तय किया गया है और लॉट साइज 1,600 शेयर है। शेयरों की लिस्टिंग 13 अप्रैल को बीएसई एसएमई पर हो सकती है। वहीं Propshare Celestia आईपीओ 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक खुला रहेगा। कंपनी इस इश्यू के जरिए रुपए 244.65 करोड़ जुटाने की योजना में है। इसका प्राइस बैंड रुपए 10 लाख से रुपए 10.5 लाख प्रति शेयर रखा गया है।

एलपीजी सिलेंडर के लिए अब लंबी वेटिंग खत्म!

नईदिल्ली। मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह है भारत में एलपीजी की अपूर्ति प्रभावित हुई है। जनता को एलपीजी की अपूर्ति के प्रभाव से बचाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिसमें से हालिया फैसला लोगों को लिए लाभकारी साबित हो रहा है। दरअसल, दिल्ली में प्रवासी मजदूर अपना आधार कार्ड और एक पहचान पत्र दिखाकर 5 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर ले सकते हैं। इसके अलावा, विभाग ने यह भी साफ किया कि दिल्ली में किसी भी तरह का कोई ऊर्जा संकट नहीं है। सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। एलपीजी की स्थिति पर नजर रखने और शिकायतें व पूछताछ लेने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग के अतिरिक्त आयुक्त, अरुण झा ने बताया कि दिल्ली में लगभग 56 लाख घरेलू एलपीजी कनेक्शन हैं।

एलपीजी और एटीएफ के बाद अब सीएनजी हुई महंगी

नईदिल्ली। देश में ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। कमर्शियल एलपीजी और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के बाद अब सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। इस बार टॉरेंट गैस ने सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया है। हालांकि अभी तक सरकारी कंपनियों की ओर से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। टॉरेंट गैस ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) के दाम में रुपए 2.50 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद आम लोगों और खासकर ऑटो-रिक्शा चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका है। इससे पहले नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया था, जबकि सरकारी तेल कंपनियों ने अभी तक अपने रेट स्थिर रखे हैं। 1 अप्रैल से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है।

खुदरा महंगाई 6% से अधिक होने के आसार: एचएसबीसी

नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बने रहने पर खुदरा महंगाई दर छह प्रतिशत से अधिक हो सकती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के तय दायरे की ऊपरी सीमा है और इससे ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। विदेशी ब्रोकरेज एचएसबीसी ने यह अनुमान जताया है। एचएसबीसी के अर्थशास्त्रियों ने एक रिपोर्ट में अपने विश्लेषण के आधार पर कहा कि यदि कच्चे तेल की कीमतों का औसत 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रहता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर छह प्रतिशत से नीचे बनी रह सकती है। अर्थशास्त्रियों ने कहा, यदि तेल की कीमतें लंबे समय तक 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रहती हैं, तो महंगाई दर छह प्रतिशत से अधिक हो सकती है।

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कामचलाऊ मॉडल को अपनाना संभव नहीं

शंकर अय्यर

भारत की सरकारें लंबे समय से नागरिकों को यह यकीन दिलाती रही हैं कि हालात बेहतर होने से पहले और बिगड़ते हैं, कि संकट एक 'फील-गुड फैक्टर' है, क्योंकि यह सिर्फ सोचने-विचारने के बजाय काम करने के लिए प्रेरित करता है। आज देश इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। भारतीयों ने ऐसी स्थितियां पहले भी देखी हैं। हर संकट के साथ दिखावटी रस्म के तौर पर नेता जमा होते हैं, कमेटियां बैठती हैं, और नौकरशाह समाधानों की एक लंबी-चौड़ी सूची पेश करते हैं। पर जो चीज ऊर्जा संकट के तौर पर शुरू होती है, वह महंगाई के जरिये धीरे-धीरे एक ऐसे आर्थिक दमघोंटू हालात में बदल जाती है, जिसे सरकारें तब तक टालती हैं, जब तक कि ऐसा कर पाना उनके लिए नामुमकिन न हो जाए।

भारत इस ऊर्जा संकट में अचानक नहीं फंसा है, बल्कि वह इसमें खुद चलकर आया है-बेपरवाही से, बिना किसी जल्दबाजी के। ट्रंप के युद्ध ने तो बस भारत के तमाम छूटे हुए अवसरों को खोलकर रख दिया है। उसके विरोधाभासों की खाई को और भी गहरा कर दिया है। अर्थव्यवस्था को जो कीमत चुकानी पड़ रही है, वह जान-बूझकर की गई अनदेखी का ही नतीजा है। अब, जब लोग एक बार फिर लंबी-लंबी कतारों में खड़े हैं, तो यहां कुछ सुझाव देना प्रासंगिक लगता है।

भारत अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आयात पर निर्भर रहा है। 1973 के तेल संकट ने तेल बिल को लगभग चार गुना बढ़ा दिया था। 1979 के संकट के कारण भारत को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक मदद लेनी पड़ी, और बॉम्बे हाई की खोज से भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया। 2014 में,

देश ने अपने कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों की जरूरत का 70 फीसदी से अधिक आयात किया था। भाजपा ने 2014 के घोषणापत्र में 'आयात बिल कम करने' के लिए ऊर्जा की खोज बढ़ाने का वादा किया था। पर आज देश की तेल आयात पर निर्भरता 88.5 फीसदी से ज्यादा है। बेशक खपत बढ़ी है, पर अहम बात यह है कि घरेलू उत्पादन घट गया है। भारत आयातित तेल के बैरल पर अपनी निर्भरता को घरेलू स्तर पर उत्पादित गीगावाट से बदलकर मजबूती बढ़ा सकता है और उसे ऐसा करना भी चाहिए। वर्ष 2005 में, किरीट पारिख की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें एकीकृत ऊर्जा नीति शामिल थी। आज, देश उन कई सिफारिशों को लागू करने में पीछे है। 63 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य के मुकाबले, आज स्थापित क्षमता 8.8 गीगावाट है, जिसमें पिछले 20 वर्षों में लगभग पांच गीगावाट की बढ़ोतरी हुई है। 2030 का 30 गीगावाट का लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी है। पर, महाराष्ट्र में जैतापुर प्रोजेक्ट पिछले 15 वर्षों से अटका हुआ है। जलविद्युत के क्षेत्र में, अनुशंसित 150 गीगावाट के मुकाबले स्थापित क्षमता 51.2 गीगावाट है। परमाणु और जलविद्युत, दोनों ही क्षेत्रों में विस्तार की राह में खराब नियामक सुधार, मंजूरी मिलने में रुकावटें और 'मेरे इलाके में नहीं' वाली राजनीतिक सोच जैसी बाधाएं खड़ी हैं।

ऊर्जा संकट का सबसे स्पष्ट उदाहरण रसोई गैस के लिए लगने वाली लंबी कतारें और उनसे जुड़े घोटाले हैं। पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के विस्तार की काफी चर्चा है, लेकिन यह अभी सिर्फ 1.8 करोड़ घरों तक पहुंचा है, जबकि एलपीजी कनेक्शन 33.3 करोड़ हैं। सच तो यह है कि पीएनजी भी होर्मुज संकट से अछूती नहीं है। असल में भारत ने विकल्पों को तैयार नहीं किया। रसोई गैस के लिए बायोगैस संयंत्र के उपयोग का विकल्प है, खासकर उन राज्यों में जहां, दो-तीन फसलें होती हैं और पराली को जला दिया जाता है। इसके अलावा, सौर ऊर्जा का भी विकल्प है। इंडियन ऑयल ने 'सूर्य नूतन' नाम का एक सौर चूल्हा पेश किया है, जिसे 'पीएम सूर्य घर' रूफटॉप प्रोग्राम से जोड़ा जा सकता है और 'उज्ज्वला योजना' के तहत दिया जा सकता है। एलपीजी से सौर ऊर्जा की ओर बदलाव से उपयोगकर्ताओं और सरकार, दोनों का बोझ कम होगा।

सरकारी जमीन पर कांग्रेस नेताओं का कब्जा: डॉ. मार्कण्डेय

कार्रवाई नहीं करने पर भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना

रायपुर। आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोढ़ी में सरपंच, सचिव और उपसरपंच ने मिलकर शासकीय जमीन का अवैध क्रय-विक्रय किया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में भाजपा ने फर्जी खरीद-फरोख्त में शामिल कांग्रेस पदाधिकारी-कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर पार्टी पर निशाना साधा है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. मार्कण्डेय ने शनिवार को यहाँ एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यलय में आहूत पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस अवैध खरीदी बिक्री में तत्कालीन पंचायत सचिव, सरपंच, उपसरपंच की मिलीभगत है। कांग्रेस पदाधिकारी द्वारा की गई अवैध खरीदी-बिक्री को लेकर मंदिरहसौद थाना क्षेत्र में इसकी शिकायत भी की गई है, और प्रशासनिक स्तर पर इसकी जाँच भी हो रही है।

डॉ. मार्कण्डेय ने बताया कि ग्राम गोढी में पूर्व सरपंच गोपाल धीवर वर्तमान में कांग्रेस सेक्टर प्रभारी आरंग हैं, और उनकी पत्नी वर्तमान में जनपद सदस्य हैं। इनके द्वारा गांव के गैर निवासी के नाम पर शासकीय भूमि दर्ज की गई है। प्रगति मिश्रा पति अनुज मिश्रा के नाम लगभग 4 एकड़ शासकीय भूमि बिना कब्जा के अवैधानिक रूप से पंचायत में प्रस्ताव पारित कर दे दी गई है। यह शासकीय भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा किया गया है।

मंदिर हसौद नगर पालिका में वार्ड क्र-12 से कांग्रेस पार्षद अनुज मिश्रा पेशे से अधिवक्ता है, जिसे गलत तरीके से 20 वर्ष से काबिज दिखाकर जमीन आबंटन की गई है, वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आरंग मे महामंत्री के पद पर काबिज प्रवीण सिंह ने भी अवैध तरीके से शासकीय भूमि पर कब्जा किया है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री डा. मार्कण्डेय ने कहा कि शासकीय भूमि का गलत तरीके से पट्टा बनाकर उसकी खरीदी-बिक्री की गई है। जो लोग इस घटना में संदिग्ध हैं, अभी फरार हैं। कांग्रेस ने अभी तक अपने पदाधिकारियों के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी होने के नाते उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो अपराध को बढ़ावा देकर अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती रही है।

डॉ. मार्कण्डेय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस बन गई है। इसका उदाहरण देते हुए सूरजपुर जिले की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि सूरजपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा एक परिवार की हत्या कर दी जाती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कांग्रेस ने नहीं की है।

मुख्यमंत्री साय का बड़ा दावा, बंगाल में भाजपा की जीत पक्की

रायपुर। पश्चिम बंगाल दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार शाम रायपुर में बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में जनता टीएमसी सरकार के खिलाफ है और इस बार भाजपा की जीत सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि वे झारग्राम जिले में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए और चार विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रैली की। उन्होंने जनता से वोट देने की अपील की। रैली ऐतिहासिक थी और बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें भाग लिया। सीएम साय ने कहा कि टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी के खिलाफ जनता में काफी आक्रोश है। आम जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और पश्चिम बंगाल की बेटियों और बहुओं को सम्मान नहीं मिल रहा। यही कारण है कि इस बार भाजपा की जीत पक्की है। वहीं, सीएम साय ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने 2026 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार गिराने की बात कही थी और बंगाल चुनाव जीतने के बाद उनका अगला लक्ष्य दिल्ली की सत्ता होना है।

लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में उमड़े जनसैलाब और हर नामांकन रैली में भारी भीड़ देखकर ममता बनर्जी विचलित हैं। जनता का यह आक्रोश देखकर वे अब इस तरह के बयान दे रही हैं। सीएम साय ने जोर देकर कहा कि भाजपा की योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति जनता का उत्साह पश्चिम बंगाल में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं और भ्रष्टाचार तथा कार्यप्रणाली में नाकामी से तंग आ चुके हैं। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने मत से लोकतंत्र और विकास की दिशा में योगदान दें।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारग्राम जिले की रैलियों में महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी यह दर्शाती है कि लोग भाजपा के प्रति समर्थन जताने के लिए तैयार हैं। उन्होंने टीएमसी सरकार के फैसलों और प्रशासनिक नाकामियों पर भी कटाक्ष किया। साय ने यह स्पष्ट किया कि इस चुनाव में भाजपा की जीत निश्चित है और ममता बनर्जी को जनता का विरोध झेलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल पहले से ही गरम है और सीएम साय की यह टिप्पणी भाजपा और टीएमसी के बीच प्रत्याशियों और समर्थकों में उत्साह और तनाव दोनों बढ़ा सकती है।

आरटीई पर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन का बड़ा फैसला

छह हजार से ज्यादा स्कूलों ने एडमिशन देने से किया इनकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देने का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन के इस फैसले से राज्य के 6 हजार से ज्यादा निजी स्कूलों में आरटीआई के तहत एडमिशन प्रक्रिया प्रभावित होगी।

एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि सरकार द्वारा आक आरटीआई के तहत दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि में लंबे समय से बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे निजी स्कूलों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। राजीव गुप्ता ने आगे कहा कि स्कूल प्रबंधन ने अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन भी किया, लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। अब यह कदम असहयोग आंदोलन के तहत उठाया गया है और अब निजी स्कूल ऋक्षश्व के तहत आवंटित विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देंगे। एसोसिएशन का कहना है कि मजबूरी में यह निर्णय लेना पड़ा है। इस फैसले से हजारों गरीब और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा पर सीधा असर पड़ सकता है, जो ऋक्षश्व के तहत निजी स्कूलों में दाखिला पाने की उम्मीद लगाए बैठे थे।

भाजयुमो ने की उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात

रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अर्पित सूर्यवंशी के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ को नक्सली मुक्त बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का आभार व्यक्त किया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष अर्पित सूर्यवंशी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ लगातार नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। बस्तर संभाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बस्तर में रहकर बस्तर को नक्सली मुक्त करने की दिशा में अद्भुत कार्य किया है। छत्तीसगढ़ को नक्सली मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी एवं उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा जी का पुन: आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष अमन प्रताप सिंह, प्रदेश मंत्री विशाल पाण्डेय, भाजयुमो कन्यशक्ति अन्नू चटर्जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष पिंटू साहू, जिला महामंत्री शंकर साहू, आशीष आहूजा, गुरमीत सिंह, राहुल राव, जितेंद्र साहू, भरत कुंडे, राजेश तांडी, खेमा सागर, विशाल शुक्ला, अनुराग साहू, शुभंकर द्विवेदी, राजन शर्मा, श्लोक शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती को समरसता दिवस के रूप में मनाएगी भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पार्टी की स्थापना दिवस 6 अप्रैल तथा महान समाज सुधारक डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को समरसता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के निवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1000 लोगों के लिए समरसता भोज का भव्य आयोजन किया जाएगा।

इस समरसता भोज में छत्तीसगढ़ प्रदेश के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी तथा स्थानीय गणमान्य नागरिक सम्मिलित रहेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों तक पहुंचाना तथा डॉ. अंबेडकर जी के समतामूलक समाज के सपने को साकार करने की दिशा में एक छोटा लेकिन सार्थक कदम उठाना है।

झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ब्रिजेश अग्रवाल ने बताया कि यह आयोजन केवल भोजन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सामाजिक सद्भाव, एकता और पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ झुग्गी-झोपड़ी के हर परिवार तक पहुंचाने के साथ-साथ हम सामाजिक समरसता को भी मजबूत कर रहे हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों से प्रेरित होकर हम सब मिलकर एक समृद्ध और समरस समाज का निर्माण करेंगे। इस आयोजन में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के अलावा रायपुर जिले के भाजपा पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, बूथ कार्यकर्ता तथा स्थानीय झुग्गी बस्तियों के निवासी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। बैठक में प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, जिला महामंत्री गुंजन प्रजापति, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अजीत सेनापति, राजेश रिछारिया, रोहित राय उपस्थि रहे।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

अफीम की खेती को सरकार का संरक्षण साबित हो गया: बैज

रायपुर। दुर्ग जिले के समोदा में बहुचर्चित अवैध अफीम की खेती को मक्का बताने पर निलंबित की गई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को जांच रिपोर्ट आए बिना ही सेवा में बहाल किए जाने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि गजब सुशासन है? पहले दिन से ही यह सरकार पूरे मामले में जांच की दिशा को भटकाने का काम कर रही है। मुख्य आरोपी भाजपा नेता विनायक ताम्रकार को एफ आई आर में तीसरे नंबर पर सह आरोपी बनाया ताकि ट्रायल के दौरान संदेश का लाभ देने की गुंजाइश बनाई जा सके, उसके द्वारा रखे गए कृषि मजदूर विश्नोई को मुख्य आरोपी बता दिया गया जिस पर किसी को यकीन नहीं, कार्यवाही के तीन दिन पहले कंटेनरों में भरकर अफीम के फल कहां भेजे गए आज तक पता नहीं चल पाया, अफीम के पौधे को गेहूं और मक्का का फसल बताने वाले कृषि विस्तार अधिकारी को अब विभागीय जांच रिपोर्ट आने से पहले ही बहाल किया जाना इस सरकार की दुर्भावना को प्रमाणित करता है। पूरे मामले के सरगना भाजपा नेता विनायक ताम्रकार को इस सरकार में कृषक रत्न सम्मान मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्या यही मोदी की गारंटी है।

सरकार 3 माह का चावल देने का प्रोपोगंडा कर रही : शुक्ला

रायपुर। सरकार द्वारा 7 अप्रैल से राशन दुकानों से एकमुश्त तीन माह का चावल दिये जाने पर सवाल खड़ा करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछले पांच महीने से सरकार राशन दुकानों को नियमित राशन तो पहुंचा नहीं पायी है। पांच माह से राशन कार्ड धारियों को चावल नहीं मिल रहा है और सरकार तीन महीने का चावल एकमुश्त देने का ढिंढोरा पीट कर चावल उत्सव मनाने जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि अभी तक दुकानों में मात्र 30 प्रतिशत चावल ही उपलब्ध है, जब दुकानों तक चावल नहीं पहुंच पाया है तो उपभोक्ता को कैसे चावल देगी सरकार? प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह सरकार का जनविरोधी कदम है, सरकार नहीं चाहती कि सभी को राशन देना पड़े, इसलिए केवाईसी का बहाना कर राशन वितरण रोक दिया गया है। 32 लाख उपभोक्ताओं के राशन कार्ड केवाईसी के नाम पर काट दिया गया। सरकार बनने के बाद सभी राशन कार्ड नए सिरे से बनाए गए थे उनमें मुख्यमंत्री अपनी फोटो छपवाए थे, जब दो साल पहले राशन कार्ड बनाए गए, बनाते समय भी आधार कार्ड लिया गया था फिर उनको अचानक क्यों रद्द किया गया।

आरटीई में गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है: ठाकुर

रायपुर। सरकार के अनिर्णय क्षमता के कारण आरटीई में निजी स्कूलों में गरीब बच्चों की भर्ती में हो पा रही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार की अनिर्णय क्षमता निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी की मांग और भर्ती नियम में बदलाव के विवाद के चलते गरीब बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। भाजपा सरकार गरीब माता पिता के बच्चों के निजी स्कूलों में पढ़ने के सपना को कुचल रही है।पहले आरटीई के भर्ती नियम में बदलाव कर निजी स्कूलों में नर्सरी को नही बल्कि पहली कक्षा को प्रवेश कक्षा माना गया जो सरासर गलत है। जबकि स्कूल की प्रथम कक्षा अगर नर्सरी है तो भर्ती उसी कक्षा से शुरू होगी। क्योकि निजी स्कूलों में जो बच्चे खुद के खर्च से नर्सरी में भर्ती होते है वो प्रगति करते हुए पीपी वन/टू के बाद क्लास वन में पहुँचते है। जब क्लास वन की सीट पूर्व से शिक्षा ले रहे पीपी टू के बच्चां से भर जायेगी ऐसे में आरटीई के तहत गरीबो बच्चों के लिए सीट कहाँ बचेगा? आखिर सरकार निजी स्कूलों के फीस बढोत्तरी के मांग पर विचार क्यां नहीं कर रही है? प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना नहीं चाहती।

अंधाधुंध जंगल कटाई को छुपाना चाहती है सरकार : वर्मा

रायपुर। खनिज राजस्व में 14 प्रतिशत वृद्धि के सरकारी दावे को चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए प्राकृतिक संसाधनों की अनियंत्रित और असंतुलित लूट का प्रमाण बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि जिस अपराध के लिए इस सरकार को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, उसे उपलब्धि बताकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। मात्र 16625 करोड़ के खनिज राजस्व के लिए पूरा प्रदेश उजाड़ दिया गया, इसके एवज में लाखों करोड़ के बहुमूल्य खनिज और सैकड़ों साल में समृद्ध हुए जंगलों की आहुति दे दी गई है। हसदेव, तमनार, धमजयगढ़, रायगढ़, मैनपाट, बैलाडीला, बचेली, किरंदुल कांकेर, बस्तर और बीजापुर में हजारों एकड़ में फैले सघन जंगलों को बर्बाद कर दिया गया। अडानी, आर्सेलर मित्तल, रूंगटा और सागर स्टोन जैसे निजी कंपनी नए-नए खदाने खोल कर बहुमूल्य खनिज कौड़ियों के दाम पर उत्खनन कर रहे और बाहर के राज्यों में संचालित कारखानों में बड़े मुनाफे पर भेज रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि जंगल, जमीन, खनिज, नदियों हमारी बर्बाद हो रही है और मुनाफा भाजपा के चहेते चंद बाहरी पूंजीपति कमा रहे हैं।

सवा दो साल में सरकार ने कुछ किया नहीं : वंदना

रायपुर। भाजपा द्वारा गांव चलो अभियान चलाये जाने पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पिछले सवा 2 साल में भाजपा की सरकार ने कोई जनहित के काम किया ही नहीं, किस मुंह से गांव जाएंगे भाजपाई। जब भाजपाई गांव जाएंगे तो गांव की जनता भाजपा के नेताओं से सवा दो सालों के कामों का हिसाब मांगेगी। सरकार ने पंचायतो को मूलभूत की राशि तक दिया नहीं। गांव में विकास कार्य ठप्प पड़े है। जनता भाजपाई को सबक सिखाने इंतजार कर रही है। इसलिये भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता भी गांव चलो अभियान से कन्नी काटने वाले है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की जनता से धोखा किया है। 17 जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। 10 हजार से अधिक गोठानों को बंद कर दिया, गांव की महिला स्व-सहायता समूह की बहने बेरोजगार हो गयी है, 7 लाख किसानों का धान भाजपा सरकार ने नही खरीदा है। गांव की जनता इंतजार कर रही कि भाजपा के लोग गांव आये तो उनसे पिछले सवा दो साल का हिसाब लिया जाये। राजपूत ने कहा कि कोई सरकार सवा दो साल में ही अलोकप्रिय हो सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण साय सरकार है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया स्मार्ट शिक्षा से छत्तीसगढ़ का भविष्य होगा मजबूत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन सरकार छत्तीसगढ़ के स्मार्ट फ्यूचर की मजबूत नींव रख रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के स्कूलों में तकनीक के माध्यम से स्मार्ट लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक लैब्स, रोबोटिक्स और एआई आधारित शिक्षा शामिल है, जो शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रोचक और भविष्य उन्मुख बना रहे हैं। सीएम साय ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि नवाचार और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। स्मार्ट लर्निंग और आधुनिक तकनीकों से शिक्षण में रोचकता बढ़ी है और विद्यार्थी तेजी से सीख रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को नई तकनीकों से परिचित कराते हैं और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल से एक नई पीढ़ी तैयार की जा रही है, जो केवल अवसरों का इंतजार नहीं करती, बल्कि स्वयं नए अवसरों का सृजन करती है। यह शिक्षा प्रणाली नवाचार, कौशल और व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित है। सरकार का उद्देश्य है कि विद्यार्थी शिक्षा के साथ-साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए भी सक्षम बनें। उन्होंने यह भी कहा कि स्मार्ट क्लासेस और आधुनिक लैब्स के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद और सीखने की प्रक्रिया अधिक सहज और परिणामोन्मुख हो गई है। छात्रों को तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ समस्या समाधान, विश्लेषण और नवाचार की क्षमता भी विकसित हो रही है। इससे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो रहे हैं।मुख्यमंत्री साय ने यह जोर दिया कि शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को सोचने, सीखने और नया करने की प्रेरणा देना भी है। स्मार्ट लर्निंग और तकनीकी नवाचार से तैयार की जा रही यह पीढ़ी समाज और राज्य के विकास में योगदान देगी।

राज्य के 150 से अधिक कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों को दिया गया प्रशिक्षण

रायपुर। पश्चिम एशिया, विशेषकर ईरान में पिछले एक माह से जारी संघर्ष के मद्देनज़र पेट्रोलियम उत्पादों तथा उर्वरक निर्माण में प्रयुक्त आवश्यक कच्चे माल के आयात में व्यवधान की आशंका उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति के कारण निकट भविष्य में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता प्रभावित होने की संभावना है। इस उभरती चुनौती को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन की कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार की परिकल्पना के तहत हरित खाद, नीली-हरी शैवाल एवं जैव उर्वकों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कृषि महाविद्यालय, रायपुर के सभागार में सफलतापूर्वक किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम की तैयारी के लिए सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करना था। प्रशिक्षण का शुभारंभ मुख्य अतिथि शहला निगार तथा डॉ. गिरिश चंदेल, कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में हुआ। अपने स्वागत उद्बोधन में डॉ. चंदेल ने मृदा स्वास्थ्य सुधार एवं दीर्घकालिक कृषि स्थिरता हेतु पर्यावरण अनुकूल पोषक तत्व प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए शहला निगार ने रासायनिक उर्वरकों की संभावित कमी पर चिंता व्यक्त की तथा हरित खाद, नीली-हरी शैवाल एवं जैव उर्वकों जैसे वैकल्पिक पोषक स्रोतों को अपनाने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आगामी दो से तीन महीनों में इनके उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए तथा किसानों को पर्यावरण अनुकूल एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.